डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
22 अगस्त 2026 शनिवार

आज का मौसम
28.3 अधिकतम
23.1 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर
# दोपहर मेट्रो

Page- 7

# कांग्रेस के लिए कारगर हो सकेगा राहुल गांधी का एक्टिविस्ट वाला अवतार?

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विपक्ष के नेता कम और एक्टिविस्ट के अवतार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। पिछले महीने जंतर-मंतर और संसद के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस बल के इस्तेमाल और पैलेट गन को लेकर सवाल उठे। राहुल गांधी ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। बाद में घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी, जिसमें तीन न्यायिक सदस्य और दो पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना संसद मार्ग थाने पर धरना देना राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में आए बदलाव का संकेत देता है। पैलेट गन से घायल साहिल नामक युवक की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद धरना समाप्त हुआ। बिना अनुमति धरना देने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई। महीने भर के भीतर प्रधानमंत्री आवास से पुलिस थाने तक धरने का यह सिलसिला नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक भूमिका से ज्यादा एक्टिविस्ट वाली छवि को मजबूत करता है।

सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को यही भूमिका निभानी चाहिए? संसद देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। यहां सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास नियमों, संसदीय प्रक्रियाओं, स्थायी समितियों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहस और विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के रूप में पर्याप्त औजार हैं। लेकिन संसद में व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखने के बजाय हंगामा, बहिष्कार और संसद के बाहर मीडिया के सामने आरोपों की झड़ी लगाना कांग्रेस की रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति हाथ में लेकर सरकार पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा न करने का आरोप लगाते हैं, उसी संविधान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण संस्थागत अधिकार और जिम्मेदारियां भी दी हैं। इन अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल सड़क पर प्रदर्शन करने से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है।

मीडिया में बने रहना और राजनीतिक प्रभाव पैदा करना दो अलग-अलग बातें हैं। धरना, नारे और टकराव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां जरूर बनाते हैं, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि मतदाता का राजनीतिक भरोसा भी बढ़े। उलटे, संसद में विपक्ष की अनुपस्थिति या लगातार बहिष्कार का फायदा सत्ता पक्ष को मिल सकता है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या होगी कि विपक्ष अपने सबसे प्रभावशाली मंच पर ही अपनी बात रखने के अवसर गंवा दे। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह संसद से सड़क और फिर बूथ तक किस रणनीति के साथ लौटना चाहती है। केवल आक्रामकता राजनीतिक पुनरुत्थान का विकल्प नहीं हो सकती। संगठन, वैकल्पिक नीतियां, विश्वसनीय नेतृत्व और जमीन पर लगातार संघर्ष इन सबका स्पष्ट खाका चाहिए। कांग्रेस पर भाजपा जिस मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती है, उसका राजनीतिक जवाब भी नारों से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विश्वास अर्जित करके ही दिया जा सकता है। बहुसंख्यक समाज में अपनी जमीन मजबूत किए बिना कांग्रेस की राष्ट्रीय वापसी मुश्किल होगी। इसके लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी छवि साफ-सुथरी हो और जो पार्टी को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता दिला सकें।

आज का सवाल राहुल गांधी के तेवरों का नहीं, उनकी रणनीति का है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि उसे केवल विरोध की राजनीति करनी है या वास्तव में सत्ता का विकल्प बनना है। दोनों रास्तों के बीच फर्क बहुत बड़ा है।

### युवाओं के लिए ठोस कार्यक्रम और विश्वसनीय नेतृत्व की जरूरत

युवा असंतोष को राजनीतिक ऊर्जा में बदलना अलग बात है और उसे किसी स्वत:स्फूर्त 'युवा क्रांति' में बदल देना अलग। भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बांग्लादेश या नेपाल से अलग हैं। कांग्रेस यदि जेन-जी की ऊर्जा को अपने पक्ष में राजनीतिक शक्ति बनाना चाहती है तो उसे केवल आंदोलनों की तस्वीरों से आगे बढ़कर युवाओं के लिए ठोस कार्यक्रम और विश्वसनीय नेतृत्व देना होगा। राहुल गांधी के लिए असली चुनौती यह नहीं है कि वे कितनी बार धरने पर बैठते हैं या कितनी बार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। असली चुनौती यह है कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद के भीतर सरकार को कितनी मजबूती से घेरते हैं और बाहर कांग्रेस को कितनी ताकत से पुनर्गठित करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष से होती है। राहुल गांधी और उनकी कोर टीम को शायद यह समझना होगा कि एक्टिविस्ट की भूमिका तत्काल सुर्खियां दे सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की संस्थागत भूमिका ही दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वसनीयता और सत्ता का विकल्प तैयार कर सकती है।

### कभी रोल मॉडल थीं और आज... घूसखोरी और दबंगई के गंभीर आरोप

# एयर होस्टेस के बाद 'लेडी सिंघम' बनी नेहा पच्चीसिया अब फरार

**कटनी/भोपाल, दोपहर मेट्रो**

नीले आसमान में उड़ने वाली एयर होस्टेस से लेकर सिर पर खाकी की टोपी पहनकर 'लेडी सिंघम' का तमगा हासिल करने वाली मध्य प्रदेश पुलिस की विवादित पुलिस अधिकारी नेहा पच्चीसिया अब कानूनी शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। कभी युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं कटनी की सीएसपी नेहा रंगदारी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल फरार हैं। कभी अपनी सादगी और संघर्ष की बदौलत तारीफें बटोरने वाली इस महिला अधिकारी पर घूसखोरी, मर्डर केस के आरोपियों को लाभ पहुंचाने और दबंगई से जमीन कौड़ियों के दाम ऐंठने की निष्पक्ष विभागीय जांच में पुष्टि हुई है।

सूत्रों के अनुसार गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड होने के बाद नेहा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल वह अपने कटनी निवास पर नहीं हैं। नेहा पर सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि उसका जब्त किया गया हाइवा डंपर छोड़ने के बदले सीएसपी मैडम ने सीधे 30 हजार रुपये का नजराना वसूला। इसके बाद कुठला थाना इलाके में हुए एक कत्ल के मामले में सीएसपी पर जानबूझकर तय समय पर अदालत में चार्जशीट दाखिल न करने का आरोप लगा। समय पर चालान न होने का सीधा फायदा कत्ल के मुख्य आरोपी को मिला और उसे कोर्ट से जमानत मिल गई।

आरोपी को जमानत दिलाने के बाद असली खेल शुरू हुआ। आरोप के अनुसार, इसके बाद आरोपी पक्ष को डरा-धमकाकर उनकी जमीन को कौड़ियों के दाम अपने करीबियों के नाम पर ऐंठ लिया गया। शिकायतकर्ता आकाश उर्फ रमेश लोधी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता रमेश लोधी पर दबाव बनाकर ग्राम कन्हवारा की एक करोड़ रूपए की जमीन की रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को मारूफ अहमद हनफी के नाम 18.20 लाख रु में करा दी। आईजी द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए।

**एक करोड़ की जमीन 18 लाख में अपने करीबी को दिलवाई**

**एयर इंडिया के साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों में भी किया काम**

### काम को सराहना भी मिली

गुना में सीएसपी के रूप में पहली ही मैदानी पोस्टिंग में दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए उन्होंने एक 'महिला मोबाइल पुलिस स्टेशन' की शुरुआत की थी, जिसे जनता और विभाग से काफी सराहना मिली और उन्हें लेडी सिंघम कहा जाने लगा। महामारी के कठिन समय में जिम्मेदारी और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने के कारण उन्हें प्रशासनिक स्तर पर पहचान और सम्मान मिला।

### फिल्मी पटकथा की तरह कहानी

नेहा पच्चीसिया का अतीत किसी फिल्मी पटकथा की तरह रहा है। वह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचोर तहसील के एक साधारण गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता शिक्षक हैं और मां गृहिणी हैं। चार बहनों में सबसे बड़ी नेहा की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने बड़ा संघर्ष किया। 12वीं के बाद नेहा ने एविएशन में डिप्लोमा किया और एयर इंडिया में बतौर एयरहोस्टेस नौकरी हासिल की। उन्होंने कई विदेशी और कॉर्पोरेट एविएशन कंपनियों में भी सेवाएं दीं। 2012 से 2016 तक तैयारी के बाद 2016 में एमपीपीएससी परीक्षा में उन्होंने 20वीं रैंक हासिल की और डीएमपी बनीं। जो अफसर कल तक ग्रामीण बेटियों की रोल मॉडल बनी हुई थीं, आज वही घूसखोरी और आपराधिक साजिश जैसे संगीन मुकदमों के घेरे में आकर साख गंवा चुकी हैं।

### झारखंड की सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट, तीन इंजीनियरों की मौत

रामगढ़, एजेंसी। झारखंड के रामगढ़ के बरकाकाना में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक टरबाइन ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियर्स की झुलसने से मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी (50), बोकारो के जगेश्वर बिहार के विनीत महतो (25) और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडेय (24) के रूप में हुई है। घायल मजदूर तरुण रजवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ब्लास्ट और आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद रामगढ़ से चार-पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं।

मृतक संजीव और विनीत महतो।

## न्यूज विंडो

### जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज दो जगह छापेमारी की। यह कार्रवाई एक आतंकी मामले की जांच के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक, एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बिजबेहरा और दूरू में दो आवासीय घरों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान क्या मिला, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जांच एजेंसी की कार्रवाई और बरामदगी से जुड़ी डिटेल का इंतजार है।

### इंडिगो विमान में आई तकनीकी खराबी, त्रिची एयरपोर्ट पर लैंडिंग

चेन्नई। इंडिगो एयरलाइंस की एक और उड़ान में आई तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों की सांसें अटक गईं। त्रिची से सिंगापुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हवा में अचानक तकनीकी समस्या आ गई।127 यात्रियों को लेकर उड़ रहे इस विमान को आपात स्थिति में वापस त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। हालांकि, लैंडिंग से पहले विमान करीब ढाई घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा।

### गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर

# वाराणसी के सभी 84 घाट डूबे, छतों पर आरती व अंतिम संस्कार करना मजबूरी

**लखनऊ/नई दिल्ली, एजेंसी**

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखनऊ-बाराबंकी समेत 5 शहरों में सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में सभी 84 घाट डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी छत पर कराई जा रही है।

उधर, दिल्ली में शुक्रवार रात से रुक-रुककर बारिश जारी है। महीना खत्म होने से पहले अगस्त में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सफदरजंग मौसम केंद्र में 1 से 21 अगस्त के बीच 235.3 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि अगस्त की सामान्य बारिश 233.1 मिमी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में वीकेंड पर भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

वाराणसी में घाट पर बने 100 छोटे-बड़े मंदिर डूब गए हैं। छतों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

### मध्यप्रदेश: विंध्य की तमसा, बेलन-नैना नदी का जल स्तर बढ़ा

भोपाल। मानसून ट्रफ, चक्रवात और लो प्रेशर एरिया की वजह से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से बीते 2 दिन से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है और कई जिलों में बाढ़ आ गई है। आज भी 16 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। सतना जिले में पिछले 24 घंटे में नागौद में 6.4 इंच बारिश दर्ज की गई, जो इस मानसून सीजन में जिले में एक दिन की सर्वाधिक वर्षा है। बारिश से तमसा, बेलन-नैना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जिले में 1 जून से 21 अगस्त तक औसतन 32.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 5 इंच अधिक है।

### मुलताई में दर्दनाक हादसा

# कुबेरेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक में घुसी, तीन की मौत

**बैतूल, एजेंसी**

बैतूल जिले के मुलताई फोरलेन पर आज तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जीतू ढाबे के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके कई हिस्से अलग हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के नागपुर के समीप स्थित बुट्टी बोरी क्षेत्र के निवासी थे। श्रद्धालुओं का यह समूह सीहोर स्थित प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम के दर्शन के लिए रवाना हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। मृतकों में 42 वर्षीय दीपक और उनकी 40 वर्षीय पत्नी छाया की पहचान हो चुकी है। एक अन्य महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

## आज का कार्टून

**मेट्रो एंकर** | 21 साल की उम्र होने पर सामान्य जेल में रहकर काटने होंगे 16 साल

# दुष्कर्म के दोषी किशोर को रोजाना 2 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे पौधरोपण की सजा

**कोटा, एजेंसी**

राजस्थान के कोटा पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक और सुधारात्मक फैसला सुनाया है। अदालत ने 17 वर्षीय दोषी किशोर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा तो दी है, लेकिन उसे सुधारने का एक मौका भी प्रदान किया है। कोर्ट के आदेश अनुसार जब तक दोषी 21 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसे जेल के बजाय बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। यहां उसे रोजाना अनिवार्य रूप से 2 घंटे पढ़ाई और 3 घंटे पौधरोपण व समाज सेवा करनी होगी। कोर्ट ने दोषी की मानसिक और शारीरिक स्थिति का बारीकी से आकलन करते हुए यह अनूठा आदेश दिया है।

दोषी किशोर 21 साल की उम्र तक बाल सुधार गृह में रहेगा। साथ ही उसे प्रतिदिन 5 घंटे सुधारात्मक कार्यों में व्यतीत करने होंगे। 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसे 20 वर्ष की शेष सजा काटने के लिए सामान्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा। किशोर को प्रतिदिन 2 घंटे किसी तकनीकी या अन्य शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसकी संपूर्ण व्यवस्था सुधार गृह के अधीक्षक की ओर से की जाएगी। इसी तरह जिला वन अधिकारी या समकक्ष कार्यालय के अधीन दोषी को रोजाना 2 घंटे पौधरोपण का कार्य करना होगा। शाम को 1 घंटे किसी आश्रय स्थल या 'अपना घर' जैसी संस्था में सामाजिक कार्यकर्ता की निगरानी में निस्वार्थ सेवा देनी होगी।

### 6 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया

अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किशोर पर 6 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। न्यायपालिका का यह फैसला इस बात की नजीर पेश करता है कि किशोर न्याय का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि बाल अपराधियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करना भी है। कठोर कारावास के साथ-साथ शिक्षा और पर्यावरण सेवा का यह मेल भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नई सुधारात्मक दिशा तय करता है।

### 9वीं कक्षा में पढ़ती थी पीड़िता

घटना 16 सितंबर 2024 की है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पीड़िता और आरोपी किशोर के बीच पिछले 3-4 वर्षों से जान-पहचान थी तथा दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। वारदात की रात करीब 12 बजे पीड़िता बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गई। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी किशोर उसे बहला-फुसलाकर अपनी नानी के घर ले गया। वहां उसने पीड़िता को 4 से 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

सब्जी मंडी के सामने से शुरू हो रही परेशानी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के आगे नहीं खत्म नहीं हो रही,मिनटों का सफर बदल रहा घंटों में

# पुलिस नदारद, वाहन गुत्थम-गुत्था; करोंद से निकलें कैसे..समझ नहीं पा रहे लोग

भोपाल। दोपहर मेट्रो

करोंद सब्जी मंडी के सामने इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। मंडी के आसपास सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े किए जाने और नो-पार्किंग क्षेत्र में लगातार पार्किंग होने के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है। इसके अलावा सड़क पर आवारा पशुओं के बैठे रहने से वाहन चालकों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मंडी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही अधिक रहने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालक, ऑटो, 4 पहिया वाहन और मालवाहक वाहनों के बीच रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है।

**मंडी का गेट ही जाम, पुलिस नदारद**

### सड़क पर नजर नहीं आ रहे ट्रैफिक संभालने वाले जवान

स्थानीय रहवासियों और वाहन चालकों का कहना है कि मंडी के सामने नो-पार्किंग व्यवस्था होने के बावजूद वाहन चालक सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इसे देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान तक नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर पशुओं का भी जमावड़ा है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार बाइक सवार पशुओं के सामने आने पर गिरे भी हैं। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है।

### ..और बढ़ेगी मुश्किल

रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आगे जाम के साथ-साथ सड़क हादसों का खतरा और भी बढ़ेगा। लोगों ने नगर निगम और यातायात पुलिस से करोंद सब्जी मंडी के सामने विशेष अभियान चलाने की मांग की है।

---

जिम्मेदारों की अनदेखी से कुछ सपने हुए पूरे, लेकिन ज्यादातर अधूरे ही रह गए

# स्मार्ट सिटी...10 साल में 1000 करोड़ खर्च न शहर हुआ स्मार्ट, न लोगों में आई स्मार्टनेस

भोपाल। दोपहर मेट्रो

शहर स्मार्ट बनाने की तैयारियों के बीच 2016 से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 10 साल में जिम्मेदारों ने करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी। लेकिन जिम्मेदारों के सभी दावे जमीन पर नहीं उतर सके। जो उतरे भी, उनमें भी कई आधे-अधूरे ही हैं। दावा था कि 342 एकड़ में फैले टीटी नगर क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शहर में आईटी आधारित सेवाओं को दुरुस्त करने की योजना भी बनाई गई। लेकिन अधिकांश दावे आज धरातल पर औंधे मुंह पड़े हैं। हालांकि इस बीच कई ऐसे काम भी हुए, जिसने भोपाल की सूरत बदली है। आम लोगों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया है। लेकिन शहर पूरी तरह स्मार्ट अब तक नहीं बन सका। एकओर प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ का 'अटल पथ', 43.50 करोड़ की 2.2 किमी लंबी स्मार्ट रोड, 50 करोड़ की एमपी नगर मल्टीलेवल पार्किंग, 17 करोड़ का आइडीआरसीसी और 55 करोड़ रुपए से बने 11 कचरा ट्रांसफर स्टेशन जैसी प्रमुख बुनियादी संरचनाएं तैयार हुई हैं। लेकिन 5.36 करोड़ रुपए की साइकिलें और जर्जर साइकिल ट्रैक जर्जर हो गई। 5 करोड़ की फेल हो चुकीं अंडरग्राउंड डस्टबिन और दशहरा मैदान का अधूरा काम योजना की पोल खोल रहे हैं। 6000 से अधिक पेड़ काटकर बसाए गए इस क्षेत्र के 42 में से 18 प्लॉट ही बिक सके हैं। ह्य

### इन प्रोजेक्ट्स की ऐसी है हालत

**हाट बाजार: पब्लिक यूटिलिटी की जगह नहीं**

स्मार्ट सिटी में 6499.75 वर्ग मीटर क्षेत्र में 417 दुकानें बनाई गई हैं। इस पर 48.66 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3 मंजिला की बिल्डिंग बनाई। लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के लिहाज से कुछ नहीं है। पार्किंग व्यवस्था नहीं है।

**5.36 करोड़ की साइकिलें कहां हैं**

शहरवासियों को सेहतमंद बनाने के लिए अप्रैल 2018 में 5.36 करोड़ खर्च कर 500 साइकिलें खरीदी गई थीं। इसके लिए नर्मदापुरम रोड, स्मार्ट रोड पर ट्रैक बनाए। अब साइकिलें बंद हैं। साइकिल ट्रैक भी उखड़ गया। साइकिलें कहां हैं, यह भी बड़ा सवाल है।

**भोपाल प्लस ऐप और स्मार्ट पोल दोनों फेल**

स्मार्ट सिटी की शुरुआत में पहला प्रोजेक्ट शहर में 100 स्मार्ट पोल लगाने का था। इन स्मार्ट पोल के जरिए अभी केवल स्ट्रीट लाइट मिल रही है। ई-व्हीकल चार्जिंग, वाई-फाई और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाओं का कोई अता-पता तक नहीं है।

### 40 करोड़ रुपए की अटल पथ पर ड्रेनेज नहीं

40 करोड़ रुपए की बुलेवर्ड स्ट्रीट पर सरफेस ड्रेनेज तक का ध्यान नहीं रखा गया है। सरफेस ड्रेन के होल साइकिल ट्रैक पर हैं। इस वजह से बारिश का पानी सड़क पर बहता है और वह खराब हो जाती है। इस बार भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कई जगहों से सड़क उखड़ रही है। लगातार बारिश होने से आगे दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।

**काम जो नजर आ रहे**

**अटल पथ:** बुलेवार्ड स्ट्रीट 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाई। इसे जिसे अटल पथ नाम दिया।

**स्मार्ट रोड:** प्रदेश की सबसे महंगी 2.2 किमी लंबी सड़क 43 करोड़ 50 लाख से बनी थी।

**हाउसिंग प्रोजेक्ट:** एक फेज ही पूरा।

**कचरा ट्रांसफर स्टेशन:** 55 करोड़ से 11 कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाए।

**आईडीआरसीसी:** 17 करोड़ से आईडीआरसीसी कोरोना कॉल सेंटर यहीं बना।

**स्मार्ट पार्क:** 9 करोड़ का स्मार्ट पार्क बना।

**पार्किंग:** 50 करोड़ से एमपी नगर में तो 36 करोड़ से टीटी नगर में मल्टीलेवल पार्किंग।

**आर्च ब्रिज:** 39 करोड़ का आर्च ब्रिज बनाया।

### फेल हो गई 5 करोड़ की स्मार्ट डस्टबिन

**5 करोड़ रुपए** खर्च कर अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाई गई। लगने के बाद इन डस्टबिन की हकीकत सामने आई कि इनमें कचरा मिक्स हो रहा है। ऑटोमैटिक ढक्कन खुलने और बंद होने जैसी बातें भी शिगूफा निकलीं। बाद में स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन के बाद इसे मुक्त रखा था, यानी ये कोई काम की नहीं निकली।भोपाल में यह 100 बनने थे, इसकी जगह 30 बन सके थे।

इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी एरिया में कुल 42 प्लॉट हैं। इनमें से 18 ही बिके हैं। बताते हैं, प्लॉट बेचकर ही प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है, लेकिन रेरा समेत कई अड़चनों की वजह से प्लॉट बिक नहीं सके। इन प्लॉटों का साइज 1 से 5 एकड़ तक है। जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जिम्मेदारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी एरिया को बड़े कमर्शियल एरिया में डेवलप किया जाना है। इसलिए इनकी प्लॉट साइज छोटी नहीं की है। वर्तमान में कई बड़े प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। रेरा में नियुक्तियां नहीं होने की वजह से भी दो साल तक प्लॉट बेचने में दिक्कतें आईं। इस पर विचार किया जा रहा है।

---

प्रदूषण बोर्ड और निगम को देनी होगी रिपोर्ट

# एनजीटी ने पूछा-5 साल में शहर की हवा कैसी रही, डेटा दीजिए

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल की खराब हवा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रिपोर्ट मांगी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम को साल 2019 से अब तक के वायु गुणवत्ता का चार्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

एनजीटी की सेंट्रल जोन बैंच ने भोपाल की वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रबंधन एवं संबंधित निधियों के उपयोग से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही थी। पर्यावरणविद् राशिद खान की याचिका पर अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पैरवी की। नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी पिछले आदेश 20 मई 2026 के अनुपालन में भोपाल नगर निगम द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नगर निगम की ओर से यह तर्क रखा गया कि आवंटित एवं प्राप्त निधियों का पर्याप्त उपयोग किया गया है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पेश चार्ट के अवलोकन में पाया कि वर्ष 2024-25 में मात्र 12.44 करोड़ रुपए यानी, 21.18% निधि का उपयोग हुआ, जबकि वर्ष 2025-26 में निधि के उपयोग का कोई विवरण नहीं था। इसी तरह वर्ष 2023-24 में भी किसी कार्य के निष्पादन का विवरण नहीं पाया गया।

सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता एवं तिवारी ने निगम की अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में आपत्तियां उठाईं। एनजीटी ने आपत्तियों को लिखित में दो सप्ताह के अंदर पेश करने के निर्देश दिए।

**2019 से हवा की क्वालिटी की रिपोर्ट मागी**

2019 से अब तक वायु गुणवत्ता का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा मामले में पर्यावरणीय स्थिति की गंभीरता और निरंतर निगरानी को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को निर्देशित किया कि वह वर्ष 2019 से वर्तमान समय तक की वायु गुणवत्ता का विस्तृत स्टेटस चार्ट प्रस्तुत करें। एनजीटी ने यह विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वायु गुणवत्ता का विवरण माहवार प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न वायु गुणवत्ता मानकों और पैरामीटर्स के संबंध में अलग-अलग विवरण दिया जाए। इसके साथ ही अनुमेय मानकों का अलग चार्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

**5 साल में इतना एक्यूआई**

वर्ष 2019-20 के बीच शहर में हवा का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में रहा। वहीं, 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ट्रैफिक कम हुआ तो हवा में सुधार हुआ और एक्यूआई 52 के करीब पहुंच गया। 2021-22 में औसत एक्यूआई 107 (मध्यम श्रेणी) तो 2023-24 में एक्यूआई 98-105 के बीच रहा।

---

मप्र हाईकोर्ट से मिला था स्थगन, अब मामले में 15 सितंबर को सुनवाई

## रिहायशी क्षेत्र में 106 व्यापारियों को मिले स्टे को हटवाने के लिए नगर निगम पहुंचा अब हाईकोर्ट

भोपाल। दोपहर मेट्रो

कॉलोनी में कारोबार करने वाले 106 व्यापारियों को मप्र हाईकोर्ट से मिले स्टे ऑर्डर हटाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार के निर्देशन में एक टीम जबलपुर में वकीलों के साथ दो सितंबर को होने वाली स्टे ऑर्डर पर सुनवाई में शामिल होगी। उधर निगम ने अभी तक 7500 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 800 ने ही जवाब प्रस्तुत किया है। बाकी मामलों में 10 दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन त्योहार के मद्देनजर फिलहाल निगम इन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 15 सितंबर को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी जिसमें नगर निगम को एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करनी है। इस कार्रवाई के विरोध में रहवासी संगठन और व्यापारी दोनों ही अपने-अपने पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं।

**रहवासी आज निकालेंगे रैली**

अरेरा कॉलोनी, गुलमोहर, रोहित नगर, एमपी नगर, गौतम नगर, रचना नगर के रहवासी संगठन शनिवार को टॉर्च लाइट रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। याचिकाकर्ता पूर्णेन्दु शुक्ला व अन्य ने कहा, निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा। सरकार के दबाव में नोटिस दे रहा है। किस नोटिस का जवाब कब आएगा, किस नोटिस की समय अवधि कब खत्म हो रही है और कब दुकानें सील की जाएंगी, इसे निगम ने साफ नहीं किया है। निगम की इसी रवैये से रहवासियों की शांति छिन गई है।

## कार चढ़ाकर छात्र को जान से मारने की कोशिश, केस दर्ज

भोपाल। दोपहर मेट्रो

रंजिश में कॉलेज छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए। पांच कारों में पहुंचे दो दर्जन से अधिक युवकों ने दो छात्रों से मारपीट की। एक को कार चढ़ाकर घायल कर दिया। सूरज रघुवंशी (28) की शिकायत पर गोंवदिपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। रायसेन जिले के सिलवानी निवासी सूरज कटारा हिल्स में किराए पर रह रहा है। एमए कर रहा है। उसने बताया, शुक्रवार रात वह ओम चौबे के साथ कार से घूम रहा था। तभी कौशिक रघुवंशी ने फोन किया। कुछ देर बाद 5 कारों में दो दर्जन युवक पहुंचे। सूरज और ओम के साथ मारपीट की। एक ने ओम पर कार चढ़ा दी।

शांतिनाथ जिनालय में तप-त्याग की आराधना

## परिणामों को निर्मल और पवित्र बनाओ: मुनिश्री

**भोपाल।** श्री शांतिनाथ जिनालय जैन नगर लाल घाटी में आस्था उमड़ रही है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य उपाध्याय विश्रुत सागर महाराज व मुनि निर्वेदसागर महाराज के सानिध्य में समाजजन तप त्याग और संयम की साधना कर रहे हैं। प्रभु जिनेंद्र का अभिषेक और भक्तमर का वाचन हो रहा है। प्रवक्ता अंशुल जैन और समाज के सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ इंजीनियर ने बताया कि तत्व चर्चा ग्रंथ वाचन में बड़ी तादाद में समाजजन शामिल हो रहे हैं। वर्षायोग कलश स्थापना के मुख्य पुण्यर्जक सपन अनु सराफ पंकज सरोवर इंजीनियर हैं। मुनिश्री ने कहा, परिणामों को निर्मल पवित्र बनाओ, आचार्य विशुद्ध सागर की आराधना में अर्ध अर्पित किए।

## ड्यूटी खत्म कर घर लौटे, सुबह आया अटैक, एसआई की मौत

भोपाल। दोपहर मेट्रो

बजरिया थाने में पदस्थ 58 वर्षीय सब इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा की शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह बजरिया थाना क्षेत्र के सेमरा में परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार रात करीब 10 बजे ड्यूटी पूरी करने के बाद वह घर लौटे थे। सुबह करीब सात बजे उठने के बाद उन्होंने चाय पी। इसके कुछ देर बाद कमरे में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए थे, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी में डाक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। एसआई की मौत पर पुलिस विभाग ने शोक जताया है।

---

**मेट्रो एंकर** अध्यात्म अब कॅरियर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री की शिक्षा लेने वाले बढ़े

# सोच बदली...युवा सीख रहे संस्कृत, बेटियां बन रहीं कथावाचक

भोपाल। दोपहर मेट्रो

एक दौर था, जब संस्कृत और शास्त्रों की पढ़ाई युवा पसंद नहीं करते थे। इसे व्यक्ति और वर्ग विशेष तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ अब युवाओं की पसंद भी बदलती जा रही है। युवाओं के बड़े वर्ग में अब युवतियों को संस्कृत भाषा पसंद आ रही है।यही कारण है कि वे इस क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि इसे कॅरियर के रूप में भी चुन रही हैं। केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से कई बेटियां आचार्य की पढ़ाई कर रही हैं। कई ने पढ़ाई पूरी कर व्यास गद्दी को अपना लिया। कोई कथा-वाचन कर रही है तो कोई पीएचडी कर संस्कृत के क्षेत्र में काम करना चाहती है।

तपस्या तिवारी

**कथावाचक बन गईं**

तपस्या तिवारी केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री कर रही हैं। परिवार में संस्कृत या कथा-वाचन की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। बचपन से भक्ति की ओर झुकाव था। मंदिरों में भजन-मंडली और पूजा में हिस्सा लेते-लेते कथावाचक बन गईं। वे कई जिलों में कथाएं भी कर चुकी हैं।

तुलसी रैकवार

**संस्कृत को आगे बढ़ाएंगी**

तुलसी को संस्कृत में पहले से रुचि थी। माता-पिता भी चाहते थे कि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़े। रुचि के चलते तुलसी ने संस्कृत को पढ़ाई और कॅरियर का माध्यम चुना है। वे कहती है, इसी फील्ड में पढ़ाई कर भाषा का दायरा बढ़ाएंगी, ताकि यह प्राचीन भाषा युगों तक जीवित रहे।

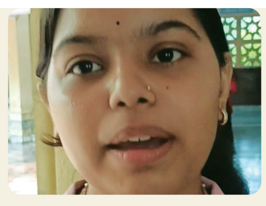

ऊषा व्यास

**पीएचडी संस्कृत से करेंगी**

ऊषा ने इसी साल संस्कृत विवि में प्रवेश लिया है। इस भाषा के प्रति बचपन से उसकी रुचि रही। कहती हैं, संस्कृत सिर्फ विषय नहीं है। यह हमारी संस्कृति-ज्ञान परंपरा की आधार भाषा है। वे आचार्य की डिग्री के बाद इसी में पीएचडी करेंगी। इस भाषा को अगली पीढ़ी के लिए आसान बनाएगी।

**..इसलिए बन रहे कथावाचक**

**दर्शन से प्रभावित:** युवाओं में संस्कृत भाषा के प्रति बढ़ती रुचि और कथावाचक बनने के बढ़ते क्रेज के पीछे सांस्कृतिक पुनरुत्थान, करियर के नए अवसर हैं। युवाओं में अपनी जड़ों, प्राचीन ग्रंथों और भारतीय संस्कृति को लेकर जागरूक हो रहे हैं। दर्शन उन्हें प्रभावित कर रहा है।

**डिजिटल शिक्षा:** अब संस्कृत पारंपरिक गुरुकुलों तक सीमित नहीं है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स से संस्कृत सीखना आसान हुआ।

**कॅरियर और शोध:** प्राचीन पांडुलिपियों के अनुवाद, डेटा साइंस, योग विज्ञान, और अध्यापन के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। कथावाचन में कॅरियर भी नजर आ रहा है।

मैनिट ने किया सर्वे तो हुआ खुलासा

## स्कूल का रास्ता जोखिम भरा, 85% बच्चे बोले- गेट के बाहर तेज रफ्तार

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मैनिट के सर्वे में स्कूल क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर मिली। 39% बच्चे अकेले आते-जाते हैं, 85% ने तेज रफ्तार वाहनों और 35% ने हादसे का अनुभव बताया। खराब फुटपाथ व असुरक्षित क्रॉसिंग बड़ी समस्या हैं। मैनिट ने 25 किमी गति सीमा, सुरक्षित फुटपाथ-क्रॉसिंग और अलग उतरने-चढ़ने की जगह का प्रस्ताव दिया है।

दरअसल, राजधानी में बच्चों के स्कूल सफर को सुरक्षित बनाने के लिए मैनिट ने 7 नंबर बस स्टॉप चौराहे से केंद्रीय विद्यालय तक के संस्थागत स्कूल क्षेत्र का अध्ययन किया। करीब 250 बच्चों और शिक्षकों से बात की गई। प्रोफेसर राहुल तिवारी के अनुसार, सर्वे में पता चला कि 38.9 प्रतिशत बच्चे अकेले स्कूल आते-जाते हैं और 84.9 प्रतिशत विद्यार्थियों व शिक्षकों ने स्कूल गेट के बाहर वाहनों की रफ्तार तेज या बहुत तेज बताई।

स्कूल गेट पर वाहनों की भीड़, खराब फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग की कमी और सड़क पर तेज यातायात बच्चों के लिए बड़ा जोखिम बन रहे हैं। अध्ययन में 34.6 प्रतिशत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्कूल के आसपास सड़क दुर्घटना देखने या उसका सामना करने की बात कही। मैनिट ने अध्ययन के आधार पर सुरक्षित स्कूल क्षेत्र के लिए विस्तृत प्रस्ताव नगर निगम को सौंपा है। नगर निगम ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाने की सहमति दी है।

### टीकमगढ़ में उद्योग-पर्यटन को नई उड़ान, सीएम मोहन का ऐलान

# महाकाल लोक की तर्ज पर सजेगा कुंडेश्वर धाम

## उद्यमियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि टीकमगढ़ जिले में औद्योगिक और पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार स्थानीय संसाधनों और उद्यमियों की क्षमता को अवसर में बदलने के लिए हरसंभव सहयोग दे रही है। स्थानीय उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह बात टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत उद्यमियों से संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ निर्बाध बिजली, बेहतर अधोसंरचना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष ध्यान है। टीकमगढ़, जतारा और झांसी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से जिले को दूसरे राज्यों के बाजारों से भी जुड़ने का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों से औद्योगिक पार्क विकसित करने, होटल और होमस्टे शुरू करने का आह्वान किया। सरकार इन गतिविधियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की टीम जल्द क्षेत्र का दौरा करेगी।

## बेल मेटल शिल्प को मिलेगा आधुनिक बाजार

मुख्यमंत्री को टीकमगढ़ जिले के धरमपुर की प्रसिद्ध पारंपरिक बेल मेटल एवं पीतल शिल्प कला के विकास के लिए करीब 1.99 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस पारंपरिक कला को केवल विरासत के रूप में संरक्षित करने के बजाय आधुनिक अधोसंरचना, कारीगरों के सशक्तिकरण, रोजगार और व्यापक बाजार से जोड़ा जाना चाहिए। बताया गया कि पीतल शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए धरमपुरा में करीब 6.99 हेक्टेयर भूमि एमएसएमई विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे स्थानीय कारीगरों को उत्पादन बढ़ाने और अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

### पर्यटन सर्किट का दिया सुझाव

संवाद के दौरान उद्यमी गौरव जैन ने बुंदेलखंड को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ओरछा, खजुराहो और टीकमगढ़ को जोड़कर एक व्यापक पर्यटन सर्किट तैयार करने तथा टीकमगढ़ को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कुंडेश्वर को 'लोक' के रूप में विकसित करने के साथ टीकमगढ़, मोहनगढ़ और बल्देवगढ़ के किलों के संरक्षण और विकास का सुझाव भी दिया। उद्यमी राजेश साहू ने बताया कि उनकी मूंगफली प्रसंस्करण इकाई बेहतर तरीके से संचालित हो रही है और उन्हें सरकार से करीब 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है।

### करोड़ों का बजट, फिर भी थाली में खराब खाना

# प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में परेशान छात्राएं आठ किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

सरकारी संस्थानों में अव्यवस्था के पीछे अक्सर बजट की कमी को कारण माना जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में तस्वीर इसके उलट है। यहां प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह 1,740 रुपये का मैस बजट निर्धारित है और सरकार अनाज भी अलग से उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद कई छात्रावासों में घटिया भोजन, खाने में कीड़े और दूषित पेयजल की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रदेश में 1,544 शासकीय कन्या छात्रावास संचालित हैं। सभी श्रेणियों के कन्या छात्रावासों में कुल 81,804 सीटें स्वीकृत हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विभाग 1,083 आश्रम छात्रावास भी संचालित करता है, जहां करीब 80 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस तरह छात्रावासों में डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राएं आवासीय शिक्षा ले रहे हैं।

इन छात्रावासों में केवल भोजन सामग्री, जैसे तेल, मसाला और सब्जी पर प्रतिमाह 14.23 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह राशि सालाना करीब 142.34 करोड़ रुपये है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में आदिवासी कल्याण के लिए 47,429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य बजट का लगभग 25.8 प्रतिशत है।

### वेंडर और प्रशासन की भूमिका पर सवाल

प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियों के पीछे स्थानीय स्तर पर वेंडर और प्रशासन के बीच अनैतिक गठजोड़ की आशंका सामने आई है। आरोप है कि कुछ मेस वेंडर घटिया सामग्री पहुंचाते हैं और वार्डन या स्थानीय अधिकारी कमीशनखोरी के चलते अनदेखी करते हैं। सरकार के 1,740 रुपये मुख्य रूप से कच्ची राशन सामग्री, तेल, सब्जी और ईंधन के लिए होते हैं। गेहूं-चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग मिलता है। इस दोहरी व्यवस्था में खराब गुणवत्ता के अनाज की आपूर्ति की आशंका भी जताई गई है। अव्यवस्था और वार्डन-अधीक्षिका के खराब व्यवहार से परेशान छात्राओं ने बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। शहडोल के धुरवार आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राएं घटिया भोजन और अव्यवस्था के विरोध में आठ किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं।

### भूमिहीनों को जमीन देने में मप्र दूसरे नंबर पर

# 96 फीसदी परिवारों को अपना घर बनाने सरकार ने दिए प्लॉट, 95.84% लक्ष्य पूरा

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में चिह्नित 38,490 भूमिहीन परिवारों में से 36,890 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। यानी 95.84 प्रतिशत, करीब 96प्रतिशत भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मिल चुकी है। प्रतिशत के हिसाब से केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे है, जहां 99.81 प्रतिशत भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दिए जवाब में दी है।**

पीएमएवाई-जी के तहत मध्य प्रदेश में कुल 38,490 ग्रामीण भूमिहीन परिवार पात्र के रूप में चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 36,890 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई, जबकि 1,600 परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाना बाकी है। इस तरह प्रदेश में 95.84त्न परिवारों को जमीन उपलब्ध हो चुकी है और 4.16त्न परिवार अभी जमीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

संख्या में मप्र चौथे, प्रतिशत में दूसरे नंबर पर भूमिहीन परिवारों को जमीन देने की कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 36,890 परिवारों के साथ देश में चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,21,202, राजस्थान में 63,925 और असम में 41,202 भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जब कुल चिह्नित भूमिहीन परिवारों के मुकाबले जमीन उपलब्ध कराने का प्रतिशत देखा जाता है तो मप्र 95.84 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है।

## प्रदेश में 57.74 लाख घरों का टारगेट

पीएमएवाई-जी के तहत मध्य प्रदेश में कुल 57,74,572 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 54,18,955 आवास स्वीकृत हुए और 43,78,398 आवास पूरे हो चुके हैं। लक्ष्य की तुलना में 13,96,174 आवास अभी अधूरे हैं। यह आंकड़ा योजना के कुल आवासों का है, इसे केवल भूमिहीन परिवारों के आवास का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। 6 अगस्त 2026 तक देशभर में पीएमएवाई-जी के तहत 5,61,919 यानी करीब 5.62 लाख भूमिहीन परिवार पात्र के रूप में चिह्नित किए गए। इनमें से 3,26,183 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई, जबकि 2,35,736 परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराना बाकी है।

### मार्च 2029 तक दो करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य

सरकार ने पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में मार्च 2029 तक अतिरिक्त दो करोड़ आवास पूरे करने को मंजूरी दी है। आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्यों को समयबद्ध लक्ष्य और पर्याप्त निधि देने, नियमित समीक्षा, डैशबोर्ड के जरिए निगरानी, कार्यशालाओं और ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवासीय जमीन देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना शुरू की थी। योजना की शुरुआत टीकमगढ़ से की गई थी। इसके तहत पात्र गरीब परिवारों को बिना किसी शुल्क के 600 वर्गफीट तक आवासीय जमीन का पट्टा देने का प्रावधान रखा गया था। योजना के जरिए ऐसे परिवारों को खुद का घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।

### टीकमगढ़ से बांटे थे 10,918 पट्टे

योजना की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ की बकपुरा ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को आवासीय भूखंडों के पट्टे वितरित किए थे। उस कार्यक्रम में 10,918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट बांटे गए थे। पूरे प्रदेश से योजना के लिए करीब 14 लाख आवेदन प्राप्त होने की जानकारी भी दी गई थी।

### सरकारी जमीन नहीं तो खरीदकर देंगे प्लॉट

योजना शुरू करते समय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत होगी, उतनी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध होगी, वहां सरकारी जमीन दी जाएगी और जहां सरकारी जमीन नहीं होगी, वहां जमीन खरीदकर प्लॉट देने की बात कही गई थी।

### केंद्र से पैसा मिलने से पहले खर्च पर रोक, केंद्रीय योजनाओं में फंडिंग पर फाइनेंस सख्त

# विभागों को खर्च राशि के दावे भेजने के निर्देश

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

राज्य सरकार ने केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में बजटीय अनुशासन के लिए विभागों के एडवांस बजट खर्च पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि ऐसी योजना में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि मिलने की प्रत्याशा में राज्य बजट से एडवांस खर्च नहीं किया जाए। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि मिलने के बाद ही संबंधित योजना में राज्य के हिस्से की राशि का आहरण किया जा सकेगा और ऐसा न करने पर सीधे तौर पर विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही विभागों से ऐसे मामलों की सूची भी मांगी गई है जिसमें राशि खर्च हुई है और केंद्र से फंड आना बाकी है।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ केंद्रीय

योजनाओं में विभागों द्वारा केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड की प्रत्याशा में राज्य बजट से एडवांस खर्च किए जाने तथा केंद्र सरकार से इसके बदले मिलने वाली राशि प्राप्त करने में देरी की स्थिति सामने आई है। इससे राज्य के संसाधनों पर अनावश्यक वित्तीय दबाव पड़ता है और इसका सीधा असर बजट के साथ सरकार की व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। वित्त विभाग ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है ताकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोका जा सके। इस आदेश का सीधा असर केंद्र से वित्त पोषित सरकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ेगा।

### सरकारी विभागों अग्रिम भुगतान नहीं कर सकेंगे

इस निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार की मदद से चलने वाली योजनाओं में केंद्र सरकार के हिस्सा का पैसा मिलने के पहले राज्य सरकार के बजट से अग्रिम खर्च नहीं किया जा सकेगा। ऐसा होने पर राज्य सरकार का पैसा केंद्र से मिलने वाले अंश के इंतजार में नहीं अटकेगा। जिन योजनाओं में खर्च करना जरूरी ही है ऐसे मामले में राज्य के हिस्से की राशि खर्च होने के तत्काल बाद संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले फंड के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। इससे केंद्र से मिलने वाली राशि में देरी कम करने का प्रयास किया जाएगा।

### लंबित केंद्रांश की निगरानी के लिए अलग सूची

अपर मुख्य सचिव ने सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को अपने विभाग की उन योजनाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिनमें केंद्र सरकार से फंड मिलना अपेक्षित है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और अधिकारियों से लगातार समन्वय कर लंबित केंद्रांश राज्य के पक्ष में हासिल कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से वेतन आहरण के मामले में स्टेट नोडल एजेंसी खाते से रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए बजट शीर्ष के निर्धारण संबंधी वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों का पालन करना होगा। जहां केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत CNA व्यवस्था के माध्यम से विभागों के बैंक खातों में राशि सीधे प्राप्त हो रही है, वहां प्राप्त राशि को संबंधित राज्य बजट की लाइनों से मिलान करते हुए मुख्य शीर्ष 1601 में कोषालय के माध्यम से तत्काल अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

### सुरक्षित वाहन चालन कोर्स विषय पर हुई कार्यशाला

**भोपाल।** सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन की नवीन तकनीकों से परिचय कराने तथा वाहन दुर्घटनाओं में पीडितों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता, केशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहम्मद शाहिद अबसार के निर्देशानुसार पुलिस परिवहन शोध संस्थान (पीटीआरआई) भोपाल में 20 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक सुरक्षित वाहन चालन कोर्स÷ विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र में मध्यप्रदेश में सड़क पर होने वाली वाहन दुर्घटनाओ एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से व वाहन दुर्घटनाओं में पीडितों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता, केशलेस उपचार सहायता उपलब्ध कराने एवं सुरक्षित वाहन चालन किये जाने के लिये निरीक्षक चालक से आरक्षक चालक स्तर के अधिकारियों को 02 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया गया।

### छात्राओं ने सैनिकों के लिए बनाई राखी, बोलीं-

# 'भैया के नाम आपकी वीरा का सलाम'

**उज्जैन।** एक हाथ में राखी, दूसरे हाथ में भाइयों के लिए पत्र और दिल से आशीर्वाद... ऐसा ही नजारा उज्जैन के एक स्कूल में दिखाई दिया। यहां छात्राओं ने देश की सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए खुद राखियां तैयार कीं और उनके प्रति अपने मन के भावों को पत्र में लिखने के साथ ही इन्हें सभी के सामने व्यक्त भी किया। सैनिक भाइयों के लिए राखी बनाने के साथ ही छात्राओं ने उनके लिए पत्र भी लिखे। इन पत्रों को आकर्षक रूप से सजाने के साथ ही छात्राओं ने उन पर अलग-अलग स्लोगन भी लिखे। एक छात्रा ने 'सैनिक भैया के नाम आपकी वीरा का सलाम' लिखा, तो वहीं 'हैप्पी रक्षाबंधन... मेरे प्यारे सैनिक भाई' भी पत्र पर लिखा गया। इन पत्रों पर छात्राओं ने राखी और भाई-बहन के फोटो भी बनाए। छात्राओं ने अपने संदेशों के जरिए सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति सम्मान, स्नेह और देशभक्ति की भावना व्यक्त की।

# नशे के नेटवर्क पर CBN का बड़ा प्रहार! 158 गिरफ्तारियां

**नीमच।** नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की मध्य प्रदेश इकाई ने वर्ष 2026 में कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ा दिया है। विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 158 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि लगातार चौथे वर्ष सीबीएन ने 100 मामलों का आंकड़ा पार किया है और इस बार अगस्त में ही यह संख्या पार हो गई।

सीबीएन की कार्रवाई अब केवल नशीले पदार्थ पकड़ने तक सीमित नहीं है। विभाग ने अवैध उत्पादन, भंडारण, ड्रग लैब, दवाओं के गैरकानूनी इस्तेमाल और अंतरराज्यीय नेटवर्क को निशाने पर लिया है। अभियान के दौरान चार ऐसी लैब का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त किया गया, जहां नशीली और नकली नशीली दवाओं के निर्माण का काम चल रहा था। कार्रवाई का असर मध्य प्रदेश से बाहर भी दिखाई दिया। गया और पुणे में भी लैब के खिलाफ कार्रवाई की गई।

### मेफेड्रोन की बड़ी खेप ने बढ़ाई चिंता

कार्रवाई के दौरान सीबीएन ने 326.402 किलोग्राम अफीम, 31,535.634 किलोग्राम पोस्ता भूसी और 223.700 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसके अलावा 1.419 किलोग्राम हेरोइन और 85.249 किलोग्राम मेफेड्रोन भी बरामद किया गया।

**मेट्रो एंकर**

### भोपाल से शुरू होगी बंदियों की काउंसलिंग व्यवस्था

# प्रदेश में जेल की सलाखों के पीछे अब होगा 'मन का इलाज'

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

मध्यप्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब सुधारात्मक व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। तनाव और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे बंदियों की पहचान कर उन्हें जरूरी मनो-सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए जेल विभाग ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के साथ समझौता किया है। जेल महानिदेशक डॉ. वरुण कपूर के मार्गदर्शन में हुए इस समझौते का उद्देश्य जेलों में केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना नहीं, बल्कि बंदियों के भावनात्मक और मानसिक सुधार को भी सुधारात्मक सेवाओं का

हिस्सा बनाना है।

इस पहल की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भोपाल स्थित क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान में बुलाकर 6 से 12 जुलाई तक सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश की अलग-अलग जेलों से 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें मेलनर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मुख्य प्रहरी और प्रहरी शामिल रहे। प्रशिक्षण में तनावग्रस्त बंदियों की पहचान, उनकी मानसिक स्थिति को समझने और काउंसलिंग के तरीके बताए गए।

प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों ने संबंधित जेलों में पहुंचकर मानसिक तनाव से गुजर रहे बंदियों की काउंसलिंग शुरू की। जेल विभाग ने इस प्रक्रिया से मिले फीडबैक और परिणामों की समीक्षा भी की। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती स्तर पर बंदियों के व्यवहार और मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। इसी अनुभव के आधार पर विभाग ने इस व्यवस्था को स्थायी और व्यापक स्वरूप देने का निर्णय लिया।

### अब तैयार होंगे 'मास्टर ट्रेनर'

समझौते के तहत जेल विभाग अपने चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर भेजेगा। वहां उन्हें विशेष मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम कराया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यही कर्मचारी जेल विभाग के भीतर मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। वे प्रदेश की दूसरी जेलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मनो-सामाजिक काउंसलिंग की तकनीक सिखाएंगे। इससे जेल विभाग के पास प्रशिक्षित मानव संसाधन का मजबूत नेटवर्क तैयार होगा।

## कूटनीतिक संदेश

कूटनीति की दुनिया में शब्द कभी-कभी अपने आकार से कहीं अधिक वजन रखते हैं। किसी राजदूत का एक वाक्य अखबार की एक खबर भर नहीं होता, वह कई बार देशों के बीच बदलते समीकरणों का संकेत भी होता है। ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का जम्मूकश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय है। कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह बिल्कुल सही बात है। उनका कहना है कि भारत लंबे समय से यही बात कहता आया है और अच्छी बात यह है कि अमेरिकी राजदूत ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा।

यहां सवाल उठता है कि क्या इसमें वास्तव में कुछ नया है? भारत के लिए जम्मू-कश्मीर की स्थिति कोई अस्पष्ट विषय नहीं है। नई दिल्ली की आधिकारिक स्थिति हमेशा स्पष्ट रही है। इसलिए किसी विदेशी राजदूत का इस बात को दोहराना भारत की जमीन पर कोई नया तथ्य नहीं जोड़ता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बात केवल तथ्यों की नहीं, कौन किस समय क्या कह रहा है, इसकी भी होती है। सर्जियो गोर का बयान उनके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दौरे के दौरान आया। उन्होंने केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा संबंधी कोशिशों की सराहना की तथा अमेरिका के यात्रा परामर्श की समीक्षा की संभावना जताई। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को खूबसूरत बताते हुए अमेरिकी नागरिकों के लिए पर्यटन और अवसरों की संभावनाओं की भी बात की। यही हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण है। कश्मीर को लगातार सुरक्षा और विवाद के चश्मे से देखने वाली अंतरराष्ट्रीय धारणा के बीच यदि कोई प्रमुख देश वहां पर्यटन, सुरक्षा और अवसरों की बात करता है, तो यह बदलाव का संकेत जरूर माना जा सकता है। किसी क्षेत्र की छवि केवल सरकारी विज्ञापनों से नहीं बदलती; जब विदेशी सरकारें अपनी यात्रा सलाह और सार्वजनिक भाषा में बदलाव करती हैं, तो उसका संदेश कहीं दूर तक जाता है। लेकिन इस उत्साह के बीच आत्ममुग्ध होने से बचना भी जरूरी है। कश्मीर की वास्तविक परीक्षा किसी राजदूत के बयान में नहीं, बल्कि घाटी की सड़कों, बाजारों, स्कूलों, रोजगार के अवसरों और लोगों के मन में है। सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी नागरिकों का भरोसा है।

# स्कूलों में छात्राओं से छेड़खानी की घटनाएं... शिक्षा के मंदिर में भरोसे का संकट

डॉ. प्रियंका सौरभ
स्तंभकार

स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार, अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। माता-पिता जब अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि शिक्षक उनके बच्चे को ज्ञान देने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इसी भरोसे की आड़ में किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी, अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है, तो चोट केवल एक बच्ची को नहीं लगती; पूरा शैक्षणिक तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है।

विद्यालयों में छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। हर घटना की प्रकृति और तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिकायत सामने आने के बाद उसे दबा देना, बच्ची को चुप कराने की कोशिश करना या संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को टालना उससे भी अधिक गंभीर समस्या है। किसी भी विद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती।

शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मूलतः विश्वास पर आधारित होता है। एक शिक्षक के पास ज्ञान के साथ-साथ अधिकार भी होता है। छात्र शिक्षक की बात को स्वाभाविक रूप से महत्व देता है और कई बार उसे अपने माता-पिता के बाद सबसे विश्वसनीय वयस्क मानता है। यही कारण है कि यदि कोई शिक्षक इस विश्वास और अधिकार का दुरुपयोग करता है तो बच्ची के लिए विरोध करना आसान नहीं होता। किशोरावस्था में बच्चे कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि किसी वयस्क का व्यवहार सामान्य है या अनुचित। डर, शर्म, सामाजिक दबाव, परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंता तथा यह भय कि उनकी बात पर विश्वास किया जाएगा या नहीं—उन्हें शिकायत करने से रोक सकते हैं। इसलिए केवल यह पूछना कि 'बच्ची ने पहले शिकायत क्यों नहीं की?' पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या विद्यालय ने ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया है जिसमें बच्ची बिना डर अपनी बात कह सके? ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक तत्व अक्सर चुप्पी होती है। कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। कुछ लोग यह सोचकर मामले को दबा देते हैं कि बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालय प्रशासन भी कभी-कभी संस्थान की छवि खराब होने की चिंता में शिकायत को आंतरिक स्तर पर समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसी चुप्पी गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यदि किसी बच्ची की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो उसे यह संदेश मिल सकता है कि उसकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण संस्थान की प्रतिष्ठा है। यह संदेश किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है।

इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को यह समझना होगा कि शिकायत करना बदनामी नहीं, बल्कि सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून तथा संस्थागत नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन की भूमिका केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था पहले से मजबूत होनी चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान उचित सत्यापन, स्पष्ट आचार-संहिता, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार के नियम तथा शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक है। विद्यालयों में बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि अच्छा और अनुचित स्पर्श क्या होता है, असहज व्यवहार की पहचान कैसे करें और किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी कैसे दें। यह शिक्षा केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूलों में ऐसी शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चा बिना भय के अपनी बात रख सके। महिला शिक्षक, प्रशिक्षित काउंसलर या अन्य विश्वसनीय वयस्क की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए क्कह्रष्टस्ह्र ष्ह्ल, 2012 मौजूद है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में यह कानून महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यालयों और उनके कर्मचारियों को इस कानून की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। किसी गंभीर शिकायत को केवल 'विद्यालय का आंतरिक मामला' मानकर दबा देना उचित नहीं है। मामले की प्रकृति के अनुसार सक्षम अधिकारियों को सूचना और सहयोग देना आवश्यक हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना भी है।

समाज में आज भी कई बार ऐसी घटनाओं के बाद सवाल बच्ची के व्यवहार, कपड़े, समय, दोस्ती या सोशल मीडिया गतिविधियों पर उठाए जाते हैं। यह सोच गलत और नुकसानदायक है। किसी बच्ची का पहनावा, उसकी बातचीत या उसका किसी शिक्षक पर विश्वास किसी वयस्क को अनुचित व्यवहार का अधिकार नहीं देता। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो अपनी स्थिति, उम्र और अधिकार का दुरुपयोग करता है। बच्चियों को सुरक्षा के नाम पर डराने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास देना होगा। उन्हें यह भरोसा मिलना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें असहज करता है तो वे बिना शर्म और भय के अपनी बात कह सकती हैं।

अधिकांश शिक्षक पूरी ईमानदारी और समर्पण से बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इसलिए कुछ लोगों के कथित या सिद्ध गलत आचरण का दाग पूरे शिक्षक समुदाय पर लगाना उचित नहीं है। लेकिन इसी कारण शिक्षकों के पेशेवर आचरण की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। शिक्षक के पास बच्चों के साथ लगातार संपर्क होता है। इसलिए उसे सीमाओं और पेशेवर मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत संदेश, अनुचित टिप्पणी, अनावश्यक शारीरिक संपर्क या एकांत में बुलाने जैसी स्थितियों को लेकर विद्यालयों में स्पष्ट नियम होने चाहिए। शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सम्मान, समानता और सुरक्षा की भावना दिखाई दे।

विद्यालय में किसी छात्रा के साथ छेड़खानी या यौन उत्पीड़न की घटना केवल एक अपराध या अनुशासनहीनता का मामला नहीं है। यह उस विश्वास पर प्रहार है जिसके आधार पर माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। इसलिए ऐसी हर शिकायत को गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से लेना जरूरी है। हमें न तो हर आरोप को बिना जांच सत्य मानना चाहिए और न ही हर शिकायत को बदनामी के डर से दबाना चाहिए। सही रास्ता है—बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, निष्पक्ष जांच करना, दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना और संस्थागत कमियों को दूर करना। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों को कितना सुरक्षित रखता है। शिक्षा का मंदिर तभी सचमुच शिक्षा का मंदिर कहलाएगा, जब वहां ज्ञान के साथ गरिमा, अनुशासन के साथ संवेदना और अधिकार के साथ जवाबदेही भी मौजूद हो। बच्चों की सुरक्षा किसी विद्यालय की प्रतिष्ठा से ऊपर है। किसी छात्रा की आवाज को दबाना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या को और गहरा करना है।

**-यह लेखक के अपने विचार हैं।**

# सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

सुनील कुमार महला
स्तंभकार

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है?

उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4% थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है?। यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम् और महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं

बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं। पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन सभी सड़क के बराबर अधिकार रखते हैं। सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

**-यह लेखक के अपने विचार हैं।**

## निशाना

### अलग पंगत हो चले...

बाबूलाल कदम

आपस में ही असंगत हो चले,
अलग पंथ अलग पंगत हो चले।
जी सके न देश धर्म के वास्ते,
दंगों में ही दिवंगत हो चले।।

## हेल्थ अपडेट

# थायरॉइड की दवा लेने के नियम का पालन जरूरी, हार्मोन लेवल पर दिखेगा असर

**देखा** जाता है कि कई लोग थायरॉयड की दवा लेने के साथ ही ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और ये एक कारण है इस दवा के ठीक तरह से काम ना करने का। अमेरिकन थायरॉइड एसोसिएशन के अनुसार हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट को थायरॉयड की दवा लेने के कुछ ही मिनटों बाद खाना-पीना नहीं चाहिए। क्योंकि सिर्फ दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दवा लेने का सही समय और दवा लेने के बाद आप क्या खाते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो दवा अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगी। इसलिए थायरॉइड की दवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है।

हाइपोथायराइडिजम के मरीजों को थायरॉइड हार्मोन की कमी को दूर करने के लिए लेवोथायरोक्सिन दवा दी जाती है। एनसीबीआई की स्टडी के अनुसार लेवोथायरोक्सिन का सेवन सुबह एक नियमित समय पर और खाने-पीने से कम से कम 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने से दवा ठीक तरह से एब्सॉर्ब नहीं होगी। क्योंकि यह दवा खाने के साथ ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाती है। इसलिए इसका सेवन सुबह खाली पेट और खाने-पीने से आधे से एक घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है।

हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों को ब्रेड ना खाने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन दवा लेने के तुरंत बाद इसके सेवन से दवा अपना काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि हाई फाइबर ब्रेड पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और लेवोथायरोक्सिन के अवशोषण में बाधा पहुंची सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं अगर ब्रेड के साथ दूध, चीज, बटर या कैल्शियम फोर्टिफाइड स्प्रेड लिया जाए, तो दवा का असर और कम हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम के कारण दवा का अवशोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। यूसीएलए हेल्थ की स्टडी के अनुसार दवा रोजाना नियमित समय पर सुबह खाली पेट लेना चाहिए।

थाइरॉइड की दवा के साथ-साथ खाने-पीने की चीजों और कब खाना चाहिए यह समझना अत्यधिक जरूरी है, जिससे दवा ठीक तरह से अपना काम कर सके, जिससे थायरॉइड हार्मोन लेवल कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। अगर दवा लेने से जुड़ी नियमों का आप पालन करते हैं और फिर भी परेशानी बनी रहती है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डॉक्टर दवा की डोज हेल्थ कंडीशन और जरूरतों के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

## कंज्यूमर अपडेट

# एयरटेल - जियो के बाद BSNL भी महंगा 225 रुपये के रिचार्ज की वैलिडिटी घटाई

**भारत** संचार निगम लिमिटेड का एक किफायती रिचार्ज प्लान अब यूजर्स के लिए महंगा हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने प्लान की कीमत में सीधा इजाफा नहीं किया है, लेकिन उसमें मिलने वाले बेनिफिट को कम कर दिया है। जिससे प्लान अपने आप ग्राहकों के लिए महंगा हो गया है। यह पहली बाक नहीं है जब कंपनी ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है। इससे पहले ही बीएसएनएल कई बार अपने रिचार्ज प्लान में मिलने वाली सुविधाओं को कम करके बिना पैसा बढ़ाए ही उन्हें ग्राहकों के लिए महंगा कर दिया है। इस बार कंपनी में 225 रुपये वाले प्लान की वैलेडिटी को कम किया है। सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं बल्कि हाल ही में एयरटेल ने भी अपने कई लोकप्रिय प्लान्स को बंद करके लोगों को महंगे प्लान की ओर थकेल दिया है। कंपनियां इस तरह धीरे-धीरे प्लान्स को बिनी कीमत बढ़ाए महंगे करती जा रही हैं।

बीएसएनएल का 225 रुपये वाला प्लान उन ग्राहकों के लिए है, जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ-साथ रोज 100 फ्री स्स्ट्र और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। प्लान में यूजर्स को रोजाना 2.5त्नक्चमोबाइल डेटा भी दिया जाता है। हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को किसी भी OTT का फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। 225 रुपये वाला यह प्लान देश भर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यह प्लान इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि इसकी वैलिडिटी कम हो गई है।

**जेब पर बढ़ेगा 225 रुपए का बोझः** रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपने इस प्लान की वैलेडिटी को 30 दिन से 28 दिन कर दिया है। इसका मतलब है कि वैलेडिटी दो दिन घटा दी गई है। आमतौर पर यह ज्यादा नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए देखें तो ग्राहकों को इससे घाटा हो गया है। 28 दिन का साइकिल होने से आपको 1 साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। इस वजह से आपको 1 ज्यादा रिचार्ज का खर्च सहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ग्राहकों की जेब पर लगभग 225 रुपये का बोझ बढ़ जाएगा।

अगर हम इस प्लान की तुलान जियो और एयरटेल से करें तो बीएसएनएल का यह प्लान जियो और एयरटेल से सस्ता है। क्योंकि एयरटेल का 28 दिन की वैलेडिटी और 2.5GB डेली डेटा वाले प्लान की कीमत 409 रुपये है। वहीं, जियो के ऐसे प्लान की कीमत 399 रुपये है। हालांकि, इन प्लान्स में BSNL पैक से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं।

## वायरल कंटेंट

# सड़क पर फर्राटा भरता नजर आया हवाई जहाज ! नजारा देख लोगों ने थाम लिया सिर

**सड़क** पर कार, बाइक और बसें दौड़ती देखना तो आम बात है, लेकिन अगर अचानक आपके सामने एक हवाई जहाज सड़क पर चलता हुआ नजर आए तो आप भी कुछ पल के लिए जरूर चौंक जाएंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में ऐसा ही एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां सड़क पर दौड़ती एक गाड़ी बिल्कुल प्राइवेट जेट जैसी दिखाई दे रही थी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, यह मामला फ्लोरिडा के मशहूर डेटोना बीच के पास का बताया जा रहा है। दो दोस्त बीच की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क पर चल रही एक अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहली नजर में उन्हें लगा कि शायद कोई छोटा प्राइवेट जेट सड़क पर आ गया है। लेकिन जैसे-जैसे गाड़ी करीब आई, पूरा मामला साफ हुआ। दरअसल, यह कोई असली हवाई जहाज नहीं था, बल्कि जेट प्लेन के लुक में तैयार की गई एक खास मॉडिफाइड कार थी।

इस गाड़ी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दूर से देखने पर यह बिल्कुल किसी छोटे प्राइवेट जेट जैसी नजर आती है। इसमें प्लेन जैसा बॉडी फ्रेम और पहिए लगाए गए हैं, जिसकी मदद से यह सड़क पर दूसरी गाड़ियों की तरह चलती है। इसका डिजाइन और फिनिशिंग इतनी शानदार है कि सड़क से गुजरते समय लोगों का ध्यान अपने आप इसकी तरफ चला जाता है। यही वजह है कि इसे देखने वाले दोनों दोस्त भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए।

दोनों दोस्तों ने इस अनोखी गाड़ी का वीडियो बना लिया।

इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो देखकर कई लोग पहले तो इसे असली हवाई जहाज समझ बैठे, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक मॉडिफाइड कार है। वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरु कर दिए। कई लोगों ने गाड़ी बनाने वाले की क्रिएटिविटी की तारीफ की। कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में सड़क पर चलने वाला 'उड़नखटोला' तक बता दिया। कुल मिलाकर, सड़क पर जेट जैसा दिखने वाला यह अनोखा वाहन लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था और अब इसका वीडियो इंटरनेट पर खूब ध्यान खींच रहा है।

## न्यूज विंडो

### हादसे रोकने की पहल... अंधे मोड़ों पर लग रहे चेतावनी बोर्ड

**गंजबासौदा।** शहर और उसके आसपास के मुख्य मार्गों पर यातायात पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत ऐसे स्थानों को चिह्नित कर वहां सांकेतिक एवं चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जहां अंधे मोड़ होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यातायात पुलिस द्वारा लगाए जा रहे बोर्डों पर सावधान, धीरे चलें जैसे संदेश लिखे गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को यह भी बताया जा रहा है कि संबंधित स्थान सड़क दुर्घटना का ब्लैक स्पॉट है। बोर्ड पर पिछले पांच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं और मौतों की जानकारी भी अंकित की गई है, ताकि वाहन चालक खतरे को गंभीरता से समझ सकें। पुलिस की इस पहल का उद्देश्य वाहन चालकों को संभावित दुर्घटना वाले स्थानों पर पहले से सतर्क करना और तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए जागरूक करना है। खासकर बारिश के मौसम में सड़कें गीली होने और दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अंधे मोड़ों पर लगाए गए चेतावनी बोर्ड वाहन चालकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। यातायात प्रभारी निरपत सिंह ने लोधी बताया कि चालकों से अपील की है कि चेतावनी बोर्ड दिखाई देने पर गति कम करें और सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान रखते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि वाहन चालकों की जागरूकता और सावधानी से भी सुनिश्चित की जा 1सकती है। सड़क दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। बोर्डों के माध्यम से वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी पहले से मिल सकेगी और वे सावधानी बरत सकेंगे।

### चार हजार एकड़ में लेमन ग्रास की खेती किसानों की फसल खड़ी, खरीदार गायब

**अनूपपुर।** जिले में लगभग चार हजार एकड़ क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को नई आय और रोजगार का सपना दिखाया गया था। लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। कई किसानों के खेतों में लेमन ग्रास की फसल खड़ी है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पर्याप्त खरीदार उपलब्ध नहीं हैं। यदि समय पर उनकी उपज नहीं खरीदी गई तो उनकी मेहनत और पूरी फसल बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच सकती है। लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के पीछे जिस निजी कंपनी की भूमिका बताई जा रही थी, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। किसानों के अनुसार कंपनी की ओर से खरीद और प्रसंस्करण को लेकर जो उम्मीदें बनी थीं, वे अब पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। कंपनी को अपेक्षित मुनाफा दिखाई नहीं दिया तो उसका क्षेत्र में संचालन कमजोर पड़ गया और कंपनी अब लगभग गायब होने की स्थिति में है। जिला प्रशासन की ओर से उक्त कंपनी को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन भी उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि कंपनी को जमीन उपलब्ध कराने, लेमन ग्रास की खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को इससे जोड़ने के दौरान प्रशासन ने खरीद, प्रसंस्करण और बाजार की दीर्घकालिक व्यवस्था का क्या आकलन किया था पिछली गर्मी में कई किसानों का लेमन ग्रास सूख गया था। अब जिन किसानों के खेतों में फसल खड़ी है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बाजार और खरीद की है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे तो लेमन ग्रास की खेती उनके लिए लाभ का साधन बनने के बजाय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।

### छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लगी आग, 3 नवजात झुलसे

**छिंदवाड़ा।** जिला चिकित्सालय में देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने अस्पताल स्टाफ और यहां भर्ती मरीजों के बीच सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि, अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में रात करीब 2 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक वार्मर मशीन में अचानक स्पार्किंग के चलते आग लग गई। हादसे के दौरान वार्मर मशीनों में तीन नवजात बच्चे मौजूद थे। आग की चपेट में आकर तीनों मासूम बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी-अभी जानकारी आई है कि झुलसने वाले तीन नवजातों में से एक की मौत हो गई है। घटना के बाद जानकारी सामने आई है कि जिला अस्पताल में जो तीन नवजात एनईसीयू वार्ड में झुलसने के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए थे, तीन बच्चों में से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई है। जान गवाने वाली बच्ची के पिता का नाम आदित्य वर्मा और माता का नाम शिवानी वर्मा निवासी चांद। गहन देखभाल के लिए वार्मर में रखते हैं। बता दें कि, नवजात बच्चों को जन्म के बाद शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने और गहन देखभाल के लिए अलग -अलग उचित समयावधि के लिए वार्मर में रखा जाता है। रात में वार्मर की हीटिंग यूनिट के फिलामेंट में अचानक स्पार्किंग हो गई, जिसके चलते मशीन में आग लग गई। आग की चपेट में आने से वार्मर में मौजूद तीनों नवजात गंभीर रूप से झुलस गए। तत्काल चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ ने बच्चों को वार्मर से बाहर निकालकर उपचार शुरू किया गाया।

### साक्षरता शिविर में विद्यार्थियों को दी कानून संबंधी जानकारी

**नरसिंहपुर।** प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में विधि विभाग छात्र छात्राओं को विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अखिलेश शुक्ला के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश मीणा एवं विधिक सहायता अधिकारी राजेश कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वालिटीयर आशुतोष स्वामी ने छात्र-छात्राओं को निशुल्क वकील की सहायता ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है उनको निशुल्क सरकारी वकील मिलता है न्याय सब के लिए एक जैसा है, इसमें नागरिकों को शीघ्र, सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाता है एवं समय समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। अगले माह 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजन होगा। इसमें सभी प्रकार के प्रकरण हल किये जाते हैं। छात्र-छात्राओं को न्यायालय की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं मौलिक अधिकार कर्तव्य, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें एवं उनके सरंक्षण के लिए योजना की जानकारी दी गई।

### मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान: हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंच रहा प्रशासन

# सरकार जनता के हित और उत्थान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है: दर्शनसिंह

**नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो**

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत बीते दिन माखन नगर में जनसंवाद शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। विभिन्न विभागों ने स्टॉल और काउंटर लगाकर नागरिकों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नागरिकों से कहा कि वे शिविर में लगाए गए विभागीय काउंटरों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लें और पात्रता के अनुसार लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के बीच पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि नर्मदापुरम जिला दो औद्योगिक क्षेत्रों वाला जिला है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिले की जनता को मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार जनता के हित और उत्थान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से विभागीय काउंटरों पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। विधायक विजयपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नर्मदापुरम जिले में विकास कार्यों को गति मिली है। मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। शिविर में 'उद्यम संवाद' का आयोजन भी किया गया। इसमें शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार शुरू करने वाले स्थानीय उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि इन उद्यमियों की सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। उन्होंने बताया कि मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य क्षेत्रों की कंपनियां विस्तार कर रही हैं, जिससे जिले में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

कलेक्टर ने नागरिकों से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भू-जल स्तर सुधारने के लिए प्रयास करने की अपील की। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान रहने की बात कही। एसपी साई कृष्ण एस. थोटा ने नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें। उन्होंने संदिग्ध लिंक, कॉल या संदेश पर व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की।

#### 4 को ऑफर लेटर, 94 का प्राथमिक चयन

शिविर में आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने स्टॉल लगाए। युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से रोजगार के अवसरों की जानकारी ली। ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ऑफर लेटर दिए गए। वहीं 94 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन किया गया।

#### पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ

शिविर में पीएमएफएमई, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, सखी स्वावलंबन, सीसीएल ऋण, लाड़ली लक्ष्मी, पीएम किसान सम्मान निधि, नामांतरण, वृद्धावस्था पेंशन, साइकिल वितरण, आयुष्मान योजना तथा कस्टम हायरिंग एवं ई-कृषि अनुदान योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। सांसदों और विधायक ने टीबी मरीजों को फूड बास्केट भी वितरित किए। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष रीना तिवारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष सावित्रीबाई परनामे, उपाध्यक्ष लालचंद यादव, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, डीएफओ गौरव शर्मा, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

### कार्रवाई: देवास के गोलीकांड में था शामिल

## जहरीली शराब तस्करी मामले में पकड़ाया आरोपी रईस पुराना बदमाश

**उज्जैन। दोपहर मेट्रो**

16 अगस्त को गुजरात को भावनगर से नकली शराब का एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें जहरीली शराब पीने से लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोगों का उपचार अस्पताल में जारी है। इस मामले में गुजरात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी और रईस पिता रफीक मोहम्मद निवासी उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस उज्जैन निवासी जुबेर और भावनगर गुजरात के ही रहने वाले शराब तस्कर गौतम सोलंकी की लगातार तलाश की जा रही है।

इस मामले में यदि बात की जाए तो सोर्स का कहना है कि रईस पिता रफीक मोहम्मद वर्तमान मे भले ही गुजरात मे रह रहा हो, लेकिन मूल रूप से वह उज्जैन के बेगमबाग का रहने वाला है और शुरुआत से ही उसका नाम अपराधों से जुड़ा रहा है। वर्ष 2018 में देवास में हुए एक चर्चित गोली कांड में भी उसका नाम सुर्खियों में रहा। इसने मुख्य आरोपी भूरा को भगाने के साथ ही तेजी से कार भी दौड़ाई थी। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए भूरा और रईस दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय रईस ने अपना निवास सारंगपुर राजगढ़ बताया था। बताया जाता है कि गोली कांड के बाद रईस उज्जैन में काम ही रहता था, लेकिन उसके जुबेर निवासी शिकारी गली हाल मुकाम बाफना पार्क कॉलोनी के साथ अच्छे संबंध हो गए थे और वह पिछले 7-8 वर्षों से उसके साथ मिलकर ही काम कर रहा था। गुजरात में नकली शराब के इस मामले मे जुबेर और रईस दोनों का नाम अब एक साथ सामने आया है।

### मंडीदीप में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई

## पारसनाथ एजेंसी से श्री रत्नागिरी गाय का 77 लीटर देसी घी जब्त

**मंडीदीप। दोपहर मेट्रो**

रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में खाद्य विभाग के अमले द्वारा मंडीदीप में खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा इंदौर मे सैंपलिंग कार्यवाही के दौरान रत्नागिरी घी के 5 सेम्पल फेल होने के बाद मध्यप्रदेश प्रशासन हुआ सतर्क मंडीदीप में शिकायत के आधार पर मंगल बाजार में स्थित पारसनाथ एजेन्सी पर छापामार कार्रवाई करते हुए रत्नागिरी गाय का 77 लीटर देसी घी जिसकी अनुमानित कीमती 37 हजार रुपये का माल बरामद करते हूंवे कार्यवाही की गई।

आमजन को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा मंडीदीप में खाद्य विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मंडीदीप में पारसनाथ एजेन्सी से श्री रत्नागिरी गाय का घी के दो अलग-अलग बैच, नोवा शुद्ध घी का नमूना लेते हूंवे सेम्पल लिए गए। इस कार्यवाही के दौरान मौजूद रहें खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र नुनइयां एवं कीर्ति मालवीय साथ मे SK दुबे उपस्थित रहें पारसनाथ एजेंसी संचालक मनोज जैन ने बताया कि मेरा माल असली है मेरी अधिकारियों से बात हो गई है मेरे सारे सैंपल पास हो जाएंगे मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र नुनइयां ने बताया कि खाद्य विभाग ने छापा मार कार्यवाही की है। नकली घी जप्त किया गया है, जो जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।

## कांवड़ यात्रा को विशाल एवं भव्य बनाने युवाओं संग विधायक ने बैठक में की चर्चा

**सिरोंज। दोपहर मेट्रो**

स्व. श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की प्रेरणा से प्रारंभ होकर प्रतिवर्षानुसार आयोजित होने वाली काँवड़ यात्रा की तैयारियों एवं यात्रा में युवाओं की भागीदारी को लेकर गुरुवार शाम को शहर की युवा तरुणाई के साथ क्षेत्रीय विधायक एवं कांवड़ यात्रा समिति के संरक्षक उमाकांत शर्मा ने यात्रा की व्यवस्था संबंधी बैठक का आयोजन शीतला माता मंदिर स्थित भवन में किया।

बैठक में नगर के विभिन्न वार्डो तथा ग्रामीण अंचल से पहुंचे युवाओं तथा आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक उमाकांत शर्मा ने श्रावण के पवित्र मास में भोलेनाथ को कांवड में पवित्र तीर्थों के जल से अभिषेक करने के महत्व से अवगत करते हुए कहा कि सनातन धर्म इसका बड़ा महत्व बताया गया है। श्रद्धा विश्वास,मर्यादा और अनुशासन के साथ चढ़ाई जाने वाली कांवड़ का पुण्य फल अवश्य मिलता है। आज अपने क्षेत्र के पवित्र धाम देवपुर में गांव- गांव से यात्राओं के माध्यम से बुजुर्ग माता बहिनें बच्चें उल्लासपूर्वक पहुँच रहे हैं। स्व. लक्ष्मीकांत शर्मा ने जनकल्याण के उद्देश्य से संकल्प लेकर इस यात्रा को अपने क्षेत्र में प्रारंभ किया था। सनातन हिन्दू एकता के लिए भी आज के दौर में इन यात्राओं की महती आवश्यकता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित युवाओं से प्रत्येक ग्राम तथा वार्डो के मोहल्लों से ट्रेक्टर-ट्राली, मोटरसाइकिल आदि से अधिक से अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया एवं जिम्मेदारियों का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि बाबा विश्वनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र समिति द्वारा श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार यह यात्रा 24 अगस्त 2026 श्रावण सोमवार को दोपहर 12 बजे से नागेश्वर शिवमन्दिर पाटीदार धर्मशाला से पूजन अभिषेक उपरांत प्रारंभ होगी । इस हेतु कावड़ियों के लिए कृषि उपज मंडी परिसर में एकत्रीकरण होगा। बैठक को समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा गण, वरिष्ठ नागरिक तथा कांवड़ यात्रा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

### बिछिया जंगल में बड़े जुआ फड़ पर पुलिस की दबिश

## छह जुआरी गिरफ्तार; चार लाख रुपए से ज्यादा का सामान जब्त

**शहोडल। दोपहर मेट्रो**

शहडोल के अमलाई थाना पुलिस ने बीती रात लुकमपुर रोड स्थित बिछिया जंगल के किनारे चल रहे बड़े जुआ फड़ पर दबिश देकर छह जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने फड़ से 30 हजार 200 रुपये नकद, चार मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन सहित चार लाख रुपये से अधिक का मशरूका जब्त किया है। मामले में कुल आठ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि लुकमपुर रोड स्थित बिछिया जंगल के पास जुआ फड़ संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अमलाई भूपेंद्र मणि पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई से जुआरियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान छह लोगों को पकड़ लिया गया और मौके से नकदी सहित वाहन व मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुनीत गौतम, उत्तम कहार, अमित चौहान, सुनील कुमार राव, दीपक चतुर्वेदी और अतीक अंसारी उर्फ जुल्ली के रूप में बताई है। वहीं, अब्दुल रहमान और अनिल मंडल की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) के तहत संगठित अपराध का मामला दर्ज किया है।

अमलाई थाना क्षेत्र से सटे अनूपपुर जिले के चाचई क्षेत्र में भी एक बड़े जुआ फड़ के संचालित होने की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोयलांचल क्षेत्र का एक बड़ा जुआरी यहां फड़ संचालित कर रहा है, जहां एक रात में कई लाख रुपये का खेल होने की बात कही जा रही है।

**मेट्रो एंकर** नरसिंहपुर जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में आयोजित हुआ नशा मुक्ति अभियान

# विद्यार्थियों को जागरुक कर नशामुक्त समाज की दिलाई शपथ

**नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो**

जिले में सहयोग युवा समिति द्वारा युवा जागरण यात्रा अभियान के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में नशा मुक्ति जन-जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन किया गया समिति के फाउंडर मेंबर फलित सिंह पटेल के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के तहत शासकीय विद्यालय झामर, बम्हौरी, नयागांव, धमना, मुराछ और इमलिया गारारू में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, प्रेरक गीत, भाषण और कविताओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि नशा किस तरह व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। छात्रों के जीवंत मंचन ने उपस्थित शिक्षकों व ग्रामीणों को गहराई से प्रभावित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात आयोजित संवाद सत्र में छात्रों ने नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु अपने नवाचारी विचार रखे। विद्यार्थियों ने कहा कि युवाओं को खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और कौशल विकास से जोड़कर इस लत से दूर रखा जा सकता है। साथ ही शिक्षण संस्थानों के आस-पास नशीली सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने की बात भी प्रमुखता से उठाई गई। फलित सिंह पटेल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवा ऊर्जा सही दिशा में लगे, तो समाज में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और अपने गांव व समाज में इसके खिलाफ अलख जगाने का आह्वान किया कार्यक्रम समापन के अवसर पर शिक्षकों, समिति के सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने जीवन में कभी भी नशा न करने और नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की सामूहिक शपथ ली।

### आशंका खत्म: डेढ़ माह बाद बाघिन की जांच रिपोर्ट निगेटिव, वन विभाग ने ली राहत की सांस, 8 जुलाई को रेस्क्यू कर भेजा था जबलपुर

# स्वस्थ बाघिन अब लौटेगी अपने घर टाइगर रिजर्व, लेकिन गुस्सा अब भी ज्यादा

**तेन्दूखेड़ा। दोपहर मेट्रो**

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से करीब डेढ़ माह पहले 8 जुलाई को रेस्क्यू कर जबलपुर भेजी गई बाघिन की जल्द घर वापसी होगी। वेटरनरी कॉलेज जबलपुर के चिकित्सकों की देखरेख में उपचार करा रही बाघिन की सेहत को लेकर बना संकट अब टल गया है। दोबारा कराई गई जांच में केनाइन डिस्टेम्पर की रिपोर्ट निगेटिव आई है इससे वन विभाग ने राहत की सांस ली है। अब बाघिन के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक रहवास यानी जंगल में वापस छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन वन विभाग से बाघिन को वापस ले जाने के संबंध में चर्चा कर रहा है।

दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाघिन को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर 9 जुलाई को जबलपुर स्थित एसडब्ल्यूएफएचएस भेजा गया था करीब डेढ़ साल की बाघिन अपनी मां से बिछड़कर जंगल में अकेली भटक गई थी लंबे समय तक भोजन और पानी नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बेहद कमजोर हो गई थी। वह स्वयं भोजन करने में भी असमर्थ थी गंभीर स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने उसे तत्काल उपचार के लिए वाइल्डलाइफ हेल्थ सेंटर पहुंचाया था रेस्क्यू के बाद से वाइल्डलाइफ हेल्थ सेंटर जबलपुर ही बाघिन का अस्थायी ठिकाना बना हुआ था, जहां चिकित्सकों और कर्मचारियों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे भोजन, दवाओं और स्वास्थ्य की नियमित जांच के साथ उसके व्यवहार पर भी नजर रखी गई। अब केनाइन डिस्टेम्पर की आशंका खत्म होने के बाद बाघिन को वापस जंगल में छोड़ने को लेकर वन विभाग और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच चर्चा चल रही है अगले कुछ दिनों में बाघिन को उसके प्राकृतिक रहवास वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़ा जा सकता है लेकिन बताया जा रहा है बाघिन का गुस्सा अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है।

### दोबारा तबीयत बिगड़ी तो बढ़ी चिंता

जबलपुर में चिकित्सकों की निगरानी में बाघिन का लगातार उपचार किया जा रहा था। उपचार के बाद उसकी सेहत में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन बीच में दोबारा तबीयत खराब होने पर चिकित्सकों ने उसकी जांच कराई। इस दौरान केनाइन डिस्टेम्पर संक्रमण की आशंका ने चिंता बढ़ा दी थी वन्यजीवों में यह गंभीर बीमारी मानी जाती है। संक्रमण की स्थिति में बाघिन को जंगल में छोड़ना दूसरे वन्यजीवों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता था। इसी वजह से वन विभाग भी उसे वापस जंगल में छोड़ने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था।

## न्यूज विंडो

### नरसिंहपुर जिले को पीएमजीएसवाई 4 में 18.61 किमी सड़कों की सौगात

**नरसिंहपुर।** मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं नरसिंहपुर विधायक प्रह्लाद सिंह पटेल के प्रयासों से नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क विकास की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -4 के अंतर्गत जिले में 18.61 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 89 लाख 49 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन सड़कों के निर्माण से करेली, गोटेगांव, साईंखेड़ा और बाबई-चीचली क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है।

जारी स्वीकृति सूची के अनुसार गोटेगांव विकासखंड में गोटेगांव-जबलपुर रोड से झांसीटोला मार्ग के लिए 1.20 किलोमीटर सड़क को मंजूरी मिली है, जिस पर 100.01 लाख रुपए खर्च होंगे। करेली विकासखंड में कुमहड़ी से मनोरिया टोला 3.40 किलोमीटर के लिए 279.65 लाख रुपए, मोहद से खिरियाटोला 1.38 किलोमीटर के लिए 113.51 लाख रुपए तथा बम्हनी से पिपरियाटोला 1.10 किलोमीटर सड़क के लिए 105.82 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह बाबई-चीचली विकासखंड में बैरागढ़ से राजीव नगर मार्ग की 0.90 किलोमीटर सड़क के लिए 89 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। वहीं साईंखेड़ा क्षेत्र में सिरसिरी से हरिजनटोला, थरेरी से थरेरी टोला, टिमरावन से चारोखर टोला, तुमड़ा से कच्छी टोला, बरहेटा से कहारटोला, अजंदा से मुआरटोला तथा ढिंगसरा से इंदिरा आवास टोला सहित विभिन्न मार्गों को स्वीकृति मिली है इसके साथ ही गोटेगांव के धुमा रोड से कुंडा बड़ा तथा बाबई-चीचली के बारहा देवरी रोड से भिम्मखेड़ी मार्ग भी शामिल हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित स्वीकृत सड़कों में कई ऐसे ग्रामीण मार्ग शामिल हैं, जो लंबे समय से स्थानीय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को मुख्य मार्गों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने तथा ग्रामीणों को स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

### परियोजना का करीब 226 किमी ट्रैक तैयार; जल्द यात्री ट्रेनों के संचालन की उम्मीद

# ब्यावरा-सोनकच्छ रेल लाइन का सफल स्पीड ट्रायल 120 किमी की रफ्तार से फोरलेन से गुजरी ट्रेन

**राजगढ़। दोपहर मेट्रो**

रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन परियोजना के तहत ब्यावरा-सोनकच्छ के बीच निर्मित 24.5 किलोमीटर लंबा रेलखंड अब यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुंबई से आए रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) गुरु प्रकाश ने दो दिवसीय निरीक्षण के बाद इस ट्रैक को ओके करार दिया है।

बीते दिन ब्यावरा स्टेशन से सोनकच्छ के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर सफल स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन जैसे ही नेशनल हाईवे फोरलेन पर बने रेलवे ब्रिज से 120 की स्पीड में गुजरी, मौके पर मौजूद अधिकारियों और ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। अब इस नए रेलखंड पर यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के लिए अंतिम औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। दो दिवसीय निरीक्षण के दौरान सीआरएस टीम ने बीते दिन सुबह 11 बजे सोनकच्छ की ओर से मोटर ट्रॉली के जरिए नए रेलखंड का सघन जायजा लिया। इसके बाद दोपहर करीब 3:35 बजे टीम ब्यावरा स्टेशन पहुंची, जहां से 120 की रफ्तार से स्पीड ट्रायल शुरू हुआ। जांच दल ने ट्रैक, 4 बड़े व 53 छोटे पुल-पुलियाओं, पीपलहेला हॉल्ट स्टेशन, समपार फाटकों, सिग्नलिंग, दूरसंचार व्यवस्था और स्टेशन यार्ड की तकनीकी बारीकियों को परखा। निरीक्षण में मिली कुछ छोटी-मोटी कमियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

### राजगढ़ से ब्यावरा के बीच का हिस्सा बाकी

276 किलोमीटर लंबी रामगंजमंडी-भोपाल परियोजना में से अब तक करीब 226 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 111 किलोमीटर के हिस्से में से 80 किलोमीटर का ट्रैक ब्यावरा-सोनकच्छ सीआरएस के साथ तैयार हो गया है। अब भोपाल मंडल में सिर्फ सोनकच्छ से कुरावर के बीच का काम शेष है। वहीं दूसरी तरफ, कोटा मंडल के 165 किलोमीटर हिस्से में से 146 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जहां रामगंजमंडी से राजगढ़ तक पहले ही सीआरएस हो चुका है। कोटा मंडल में केवल राजगढ़ से ब्यावरा के बीच का हिस्सा बाकी है।

### गुना हाइवे पर लूट, दर्शन कर लौट रहे राहगीर से लूटे नकदी

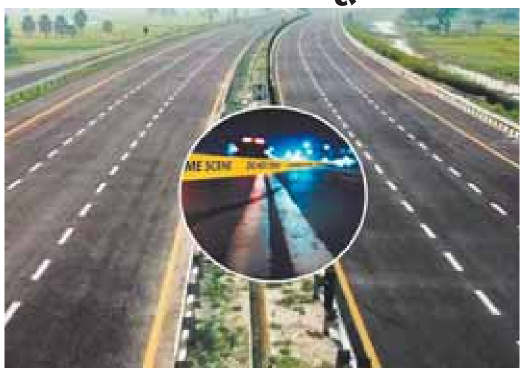

**गुना।** जिले में हाइवे पर गादेर के बोरखेड़ा गांव के जोड़ पर एक बार फिर दिनदहाड़े एक राहगीर के साथ लूट का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर से दर्शन करके लौट रहे युवक को फोन पर बात करते समय दो अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया और उसके साथ मारपीट कर जेब से 11 हजार रुपए नगद लूटकर घने जंगल में फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जाचं शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। उक्त स्थान पर करीब 15 दिन पहले भी एक इंजीनियर और उसकी मंगेतर को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट कर लूट और गैंगरेप की घटना सामने आई थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई, जिसका कामियाजा ये रहा कि, इस रास्ते के दहशतगर्दों ने महज 15 दिन के भीतर ही एक बार फिर यहां एक राहगीर को अपना शिकार बनाया है। दरअसल, जिले के ही बांसखेड़ी कैंट इलाके में रहने वाले 37 वर्षीय राकेश जाटव ने रुठियाई चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि, शाम करीब साढ़े चार बजे वो गादेर मंदिर शिवालय से दर्शन कर पैदल अपने घर की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वह ग्रीन माउंटेन के आगे बोरखेड़ा के जंगल के जोड़ के पास पहुंचे, तभी उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसे देखने के लिए वो रास्ते के एक तरफ होकर रुके और फोन पर बात करना शुरु ही की थी कि, अचानक जंगल के अंदर से 25 से 30 साल उम्र के दो अज्ञात बदमाश बाहर निकल आए।

### नवांकुर सखी हरियाली यात्रा से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

**तेंदूखेड़ा तेजगढ़। दोपहर मेट्रो**

शासन एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में ग्राम समदई में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा नवांकुर संस्था सुरसरी ज्ञान भारती शिक्षा समिति तेंदूखेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम सुंदर यादव एवं विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक दीपचंद मालवीय ने महिलाओं को पौधे भेंट किए। उन्होंने पौधों को पुत्रवत् संरक्षण देने तथा दैनिक जीवन में जल की बचत करने का आह्वान किया। पौधा वितरण के बाद गांव में जागरूकता यात्रा निकाली गई। महिलाओं एवं ग्रामीणों ने पर्यावरण बचाओ, जीवन सजाओ जैसे नारों के साथ भ्रमण कर स्वच्छता, पौधरोपण और जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में परामर्शदाता सविता विश्वकर्मा, वाइज संस्था प्रतिनिधि कृष्णा माली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा गौड़, सहायिका प्रयाग रानी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। समापन अवसर पर नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि रामकुमार राय ने अतिथियों, विभागीय कर्मचारियों, समिति सदस्यों एवं ग्राम की मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया।

### सागर में पेड़ के नीचे मिले 20 साल पुराने पांच बम आर्मी-पुलिस ने संदिग्ध एम्युनिशन को किया डिफ्यूज

**सागर। दोपहर मेट्रो**

सागर जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम बमोरी बीका में एक पेड़ के नीचे 20 साल पुराने पांच बम पड़े मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और सेना की बम डिस्पोजल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और एक संदिग्ध एम्युनिशन को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया।

जानकारी के अनुसार बीते दिन दोपहर करीब दो बजे बमोरी बीका गांव के सरपंच ने सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर को सूचना दी कि गांव के पास एक पेड़ के नीचे बम जैसी पांच वस्तुएं लावारिस पड़ी हुई हैं। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके को सील करते हुए सेना की यूनिट को सूचित किया।

सेना की बम डिस्पोजल एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि वे एम्युनिशन की कैप थीं। आर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सभी अवशेष करीब 20 साल पुराने थे। जांच में 4 बम पहले से ही डिफ्यूज (निष्क्रिय) पाए गए, जबकि 1 पीस संदिग्ध था जिसमें विस्फोटक होने की आशंका थी। सेना की टीम ने बिना जोखिम लिए संदिग्ध बम को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया।

### फायरिंग रेंज के पास का है इलाका

थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि यह इलाका आर्मी की फायरिंग रेंज के समीप स्थित है। सैन्य अभ्यास के दौरान बचे हुए पुराने एम्युनिशन के अवशेष अक्सर इस तरह बहकर या पड़े रह जाते हैं। करीब डेढ़ महीने पहले भी यहां पुराना एम्युनिशन मिला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई नया गोला-बारूद नहीं है और इनमें सामान्य रूप से विस्फोट की संभावना नहीं होती, क्योंकि इनका मैकेनिज्म काफी सुरक्षित होता है और हाई एक्सप्लोसिव विशेष प्रक्रिया से ही ऑपरेट होता है। सेना द्वारा एम्युनिशन के सुरक्षित निस्तारण के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

**मेट्रो एंकर** | अशोकनगर में 14 साल की शादी के बाद फेसबुकिया इश्क हुआ खत्म

# 'फेसबुक पर प्यार' पति को भूली पत्नी, पत्थर मारकर तोड़ा रिश्ता

**अशोकनगर। दोपहर मेट्रो**

सोशल मीडिया का प्यार जब सिर चढ़कर बोलता है, तो असल जिंदगी के मजबूत रिश्ते भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के अशोकनगर शहर के बिलाला मिल रोड पर देखने मिला। यहां फेसबुक पर हुए प्यार की खातिर एक पत्नी ने अपने 14 साल पुराने वैवाहिक जीवन को ईटों से कुचल दिया। प्रेमी के साथ जाने की जिद में पत्नी ने न सिर्फ पति पर हमला किया, बल्कि घर और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। सड़क से लेकर थाने तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का अंत आखिरकार दोनों के तलाक की सहमति पर समाप्त हुआ।

शहर की बिलाला मिल रोड कॉलोनी क्षेत्र दीपक जैन की कटनी निवासी युवती से 20 जनवरी 2012 को शादी हुई थी। 14 सालों तक जीवन की गाड़ी पटरी पर थी, लेकिन पति दीपक के मुताबिक करीब 7 महीने पहले उनकी पत्नी की जिंदगी में फेसबुक के जरिए गुना के एक युवक की एंट्री हुई। यह डिजिटल संपर्क जल्द ही गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गया और यहीं से इस हंसते-खेलते परिवार में कलह शुरू हो गई। पति का आरोप है कि उसकी जब चाहे मां की कहकर प्रेमी के पास रहने चली जाती थी। जब 27 जुलाई को वह लौटी, तो विवाद करना शुरू कर दिया। उसने घर में दीपक को बंधक बनाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साथ ही प्रेमी से पिटवाने की भी धमकियां देने लगी। हैरानी की बात यह है कि जब उसकी मां कटनी से आई तो उसने अपनी मां से भी मारपीट की। साथ ही शुक्रवार सुबह पत्नी ने पति पर ईंटों से हमला कर दिया। घर और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत और हंगामे का माहौल बन गया।

### 3 घंटे की जद्दोजहद, तलाक पर सहमति

मोहल्ले में मचे बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने के भीतर करीब तीन घंटे तक आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। घंटों की समझाइश और तीखी नोकझोंक के बाद अंततः दोनों को यह अहसास हो गया कि अब इस रिश्ते की डोर टूट चुकी है। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और कोर्ट में विधिवत तलाक की अर्जी दाखिल करने पर राजी हो गए। इस तरह एक सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड रिक्वेस्ट ने 12 साल पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए अनफ्रेंड कर दिया।

### कार्यालय थाना प्रभारी थाना गोविंदपुरा भोपाल म.प्र.

क्र. / था.प्र/गोविं/गुम इंसान- 70/26 — **दिनांक 19/08/26**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/07//26 को सूचक कुंजबाई पति गुमानसिंह उम्र 58 साल निवासी BHEL क्वाटर नंबर एन2AR सी सेक्टर सिविल ऑफिस के सामने थाना गोविंदपुरा भोपाल मोबाईल नंबर 9630914526, 8839062455, ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं उपरोक्त लिखाये पते पर रहती हूँ तथा गृहिणी हूँ मेरा लड़का गोपीचंद पिता गुमानसिंह उम्र 32 साल निवासी सदर, दिनांक 19/04/2026, माह अप्रैल के शाम 5.30 बजे बबलू ठेकेदार से पैसे लेने का बोलकर गया था जो आज दिनांक 10/07/2026 तक घर वापस नहीं आया मैने बबलू ठेकेदार से बात की थी कि मेरा लड़का पैसे लेने के लिये आपके पास आया था क्या तो बबलू ने कहा कि गोपीचंद मेरे पास नहीं आया। जिसकी तलाश मैने अपने रिश्तेदारों व आसपास मोहल्ले में किया जिसका कोई पता नहीं चला। मेरा लड़का कभी-कभी काम करने के लिये बाहर जाता है तो दो तीन माह के बाद ही काम करके घर वापस आ जाता था, जो साथ मे मोबाईल नहीं ले गया है। जिसने आज दिनांक तक घर पर कोई संपर्क नहीं किया। जिसका हुलिया कद 5 फीट 3 इंच चेहरा लंबा, शरीर इकहरा, ढाडी मुंछे निकली सिर के बाल काले व घुंघराले पैरो मे काले रंग की चप्पल पहने, नीला टीशर्ट व काला पेंट पहने है दाहिने हाथ में ओम का गुदना बना है व ऊँगलियो में गोपीचंद अंग्रेजी मे लिखा है। सूचना देने आई हूँ कार्यवाही की जावे कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 70/26 धारा पंजीवध्द कर जाँच में लिया गया।

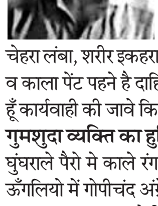

**गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया** – कद 5 फीट 3 इंच चेहरा लंबा, शरीर इकहरा, ढाडी मुंछे निकली सिर के बाल काले व घुंघराले पैरो मे काले रंग की चप्पल पहने, नीला टीशर्ट व काला पेंट पहने है दाहिने हाथ में ओम का गुदना बना है व ऊँगलियो में गोपीचंद अंग्रेजी मे लिखा है।

अतः गुमशुदा गोपीचंद की तलाश के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया थाना गोविंदपुरा भोपाल मोवाइल नंवर 7049105418 व अनुसंधान अधिकारी बीरवल प्रजापति के मोवाइल नंवर 7049104590 पर सूचित करने का कष्ट करे।

**थाना प्रभारी**
**थाना गोविंदपुरा भोपाल म.प्र.**

जी-17446/26

## टखने की चोट ने रोकी रयबाकिना की रफ्तार, विश्व नं.-1 की रेस भी बदली

# सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची इगा स्वियाटेक

**सिनसिनाटी, एजेंसी**

सिनसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में एलेना रयबाकिना और इगा स्वियाटेक के बीच मुकाबला उस समय अचानक खत्म हो गया, जब रयबाकिना को बाएं टखने में परेशानी के कारण मैच से हटना पड़ा। मुकाबले में स्वियाटेक 4-1 से आगे चल रही थीं और रयबाकिना अपनी सर्विस पर 40-15 की स्थिति में थीं। इसी दौरान एक गलत मूवमेंट के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई। रयबाकिना एक रैली पूरी करने के लिए नेट की ओर बढ़ीं, लेकिन उसके बाद उनके लिए आगे खेलना मुश्किल हो गया।

अगले अंक पर रयबाकिना अपनी पहली सर्विस को पूरी ताकत से नहीं लगा सकीं। इसके बाद मेडिकल जांच के लिए खेल कुछ देर रोका गया। जांच के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो उन्होंने मुकाबला जारी रखने के बजाय कोर्ट छोड़ने का फैसला किया। रयबाकिना ने बताया कि वह सर्विस के दौरान पैर पर ठीक से जोर नहीं लगा पा रही थीं और चलने में भी दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा कि एमआरआई के बाद चोट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

रयबाकिना ने बताया कि टखने की समस्या उन्हें पहले से परेशान कर रही थी। कनाडा में लगातार मुकाबले खेलने और सिनसिनाटी में भी दो मैच खेलने के बाद उन्हें लगा था कि वह इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन मैच के दौरान एक गलत मूवमेंट और लैंडिंग के बाद अचानक दर्द बढ़ गया। अब उनकी नजर चोट की जांच पर है, क्योंकि आगे उनके लिए बेहद अहम टूर्नामेंट इंतजार कर रहा है।

### विश्व नंबर-1 बनने का सपना भी टला

रयबाकिना के मैच से हटने का असर सिर्फ सिनसिनाटी ओपन तक सीमित नहीं रहा। आर्यना सबालेंका के चैथे दौर में हारने के बाद रयबाकिना के पास विश्व नंबर-1 रैंकिंग हासिल करने का शानदार मौका था। इसके लिए उन्हें सिनसिनाटी ओपन के फाइनल तक पहुंचना जरूरी था। हालांकि चोट के कारण

### स्वियाटेक ने जीत से ज्यादा स्वास्थ्य को दी तवज्जो

रयबाकिना के हटने के बाद स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गईं। हालांकि उन्होंने इस जीत को लेकर खुशी जताने के बजाय रयबाकिना की चोट पर चिंता व्यक्त की। स्वियाटेक ने कहा कि यूएस ओपन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन खिलाड़ी का स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रयबाकिना जल्द फिट होकर वापसी करेंगी। अब स्वियाटेक की नजर सेमीफाइनल पर है, जहां उनका सामना जेसिका पेगुला से होगा। वहीं रयबाकिना के लिए सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि चोट कितनी गंभीर है और क्या वह यूएस ओपन के लिए समय पर पूरी तरह फिट हो पाएंगी।

## टेस्ट सीरीज : यशस्वी जायसवाल ने खोज लिया कमजोरी का इलाज!

# गॉल में जिस गेंद ने किया परेशान, उसी के खिलाफ कोलंबो में जमकर अभ्यास

### तेज गेंदबाजों ने बार-बार ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गेंदें

**कोलंबो एजेंसी**

भारत और श्रीलंका के बीच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर दूसरा टेस्ट खेला जाना है। मुकाबले से पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी की एक खास कमजोरी पर जमकर काम किया है। गॉल टेस्ट में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गंवाने वाले जायसवाल ने इस बार नेट्स में उसी क्षेत्र को निशाना बनाकर अभ्यास किया। भारतीय टीम प्रबंधन भी इस कमजोरी को दूर करने के लिए उनके साथ लगातार काम करता नजर आया।

### गॉल में फिर सामने आई पुरानी समस्या

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद से जायसवाल को परेशान किया था। जायसवाल ने गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। यह कोई पहला मौका नहीं था, जब जायसवाल इस तरह की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे हों। हाल के समय में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलते हुए उनके आउट होने का सिलसिला बढ़ा है। यही कारण है कि कोलंबो टेस्ट से पहले इस कमजोरी को भारतीय टीम की तैयारी में खास जगह दी गई।

### नेट्स में गेंद छोड़ने पर दिया जोर

जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में आक्रामक बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई है। उनका टेस्ट स्ट्राइक रेट 66.24 के आसपास रहा है, लेकिन आक्रामक अंदाज कभी-कभी उनके लिए परेशानी भी खड़ी करता है। पिछले साल घरेलू टेस्ट सत्र की शुरुआत के बाद से वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों के दौरान चार बार आउट हो चुके हैं। इसके मुकाबले टेस्ट पदार्पण से लेकर पिछले साल इंग्लैंड दौरे तक करीब दो वर्षों में उन्होंने लगभग 190 गेंदों पर इस शॉट को खेलते हुए चार बार ही विकेट गंवाया था। यानी हालिया दौर में गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाकर छेड़ने की उनकी आदत ज्यादा स्पष्ट हुई है। एसएससी मैदान पर अभ्यास के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों ने जायसवाल को लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें डालकर उनकी परीक्षा ली। आकिब नबी ने शुरुआत की और ऐसी गेंदें फेंकीं, जिन पर कट शॉट खेलने का लालच आसानी से हो सकता था। लेकिन इस बार जायसवाल ने धैर्य दिखाया और गेंदों को छोड़ दिया। इसके बाद गुरनूर बरार ने भी इसी क्षेत्र में गेंदबाजी की। आगे की लेंथ पर आई एक गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को ठीक से नहीं खेल सके।

### तेज गेंदबाजों के बाद स्पिन का सामना

करीब 30 मिनट तक तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करने के बाद जायसवाल ने अपना सत्र खत्म नहीं किया। कुछ देर बाद वह दूसरे नेट्स में पहुंचे और स्पिन गेंदबाजों का सामना किया। इससे साफ था कि कोलंबो टेस्ट से पहले वह अपनी बल्लेबाजी की तैयारी को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। भारतीय टीम के लिए जायसवाल का फॉर्म बेहद महत्वपूर्ण है। वह टेस्ट क्रिकेट में टीम की आक्रामक शुरुआत का बड़ा हथियार हैं। ऐसे में अगर वह अपने शॉट चयन में थोड़ा और संयम जोड़ते हैं तो श्रीलंका के खिलाफ भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत मिल सकती है। जायसवाल के टेस्ट करियर की एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने अब तक अपने 30 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं। कोलंबो का एसएससी मैदान उनके करियर का 31वां टेस्ट स्थल होगा।

### प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बनाया दबाव

अभ्यास के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने भी ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदें डालकर जायसवाल को परखने की कोशिश की। हालांकि, इस बार भारतीय बल्लेबाज पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दिए। उन्होंने गेंद के पीछे जाने और जबरन शॉट लगाने के बजाय उसे छोड़ने को प्राथमिकता दी। आकिब नबी और गुरनूर बरार ने राउंड द विकेट से भी इसी रणनीति को आजमाया। इसके बावजूद जायसवाल ने अपना संयम नहीं खोया। भारतीय तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी अभ्यास के दौरान इस प्रक्रिया का हिस्सा बने।

### कोच गंभीर से भी हुई बातचीत

जायसवाल नेट्स में देवदत्त पडिक्कल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से बातचीत भी हुई। इसके बाद जब जायसवाल दोबारा अभ्यास के लिए उतरे तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के खिलाफ अपने फैसले पर विशेष ध्यान दिया। सबसे खास बात यह रही कि एक समय के बाद उन्होंने उस क्षेत्र में जाने वाली गेंदों का पीछा करना लगभग बंद कर दिया।

## अल्कारेज से संभावित महामुकाबला भी टला

# यूएस ओपन से पहले टेनिस जगत को झटका, चोट के चलते हटे नंबर-1 सिनर

**न्यूयार्क, एजेंसी**

साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से पहले टेनिस जगत को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने दाएं घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। 25 वर्षीय इटैलियन खिलाड़ी ने बताया कि वह 30 अगस्त से शुरू होने वाले मुख्य दौर तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। उनके इस फैसले से यूएस ओपन का रोमांच भी फीका पड़ गया है, क्योंकि अब फैंस को सिनर और कार्लोस अल्कारेज के बीच संभावित मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा।

सिनर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह अपनी टीम और मेडिकल स्टाफ के साथ लगातार चोट से उबरने पर काम कर रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यूएस ओपन से हटना ही सही फैसला है। न्यूयॉर्क में खेलने को लेकर वह काफी उत्साहित थे, इसलिए टूर्नामेंट से बाहर होना उनके लिए निराशाजनक है। सिनर पिछले कुछ दिनों से मोंटे कॉर्लो में अभ्यास कर रहे थे। कोर्ट पर वापसी के बाद उन्हें महसूस हुआ कि घुटने की समस्या से पूरी तरह उबरने के लिए अभी और समय की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने मॉन्ट्रियल और सिनसिनाटी के हार्ड कोर्ट टूर्नामेंटों से भी दूरी बनाई थी। ये दोनों प्रतियोगिताएं यूएस ओपन की तैयारियों के लिहाज से

### विंबलडन जीतने के बाद नहीं खेला कोई टूर्नामेंट

सिनर ने पिछले महीने विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार ऑल इंग्लैंड क्लब की ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद चोट के कारण वह प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर रहे। विंबलडन की जीत उनके करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब भी थी। सिनर के हटने से कार्लोस अल्कारेज के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित भिड़ंत भी टल गई है। दोनों की प्रतिद्वंद्विता हाल के वर्षों में पुरुष टेनिस की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में रही है। 2025 में दोनों लगातार तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने-सामने पहुंचे थे।

## बीपीएल पर लगा ब्रेक, घाटे और विवादों से परेशान बांग्लादेश बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

ढाका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देश की सबसे बड़ी घरेलू टी20 लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर बड़ा फैसला किया है। लगातार बढ़ते आर्थिक नुकसान, फ्रेंचाइजी की ओर से नियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक परेशानियों के बीच इस साल बीपीएल का आयोजन नहीं किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के बजाय पहले इसकी पूरी संरचना को दुरुस्त करना जरूरी है। बीसीबी अध्यक्ष तमीम इकबाल ने लीग को फिलहाल रोकने की पुष्टि करते हुए कहा कि बीपीएल में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में इसका संचालन हुआ है, उससे बोर्ड को आर्थिक फायदा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। उनके मुताबिक, पिछले दो साल में बीपीएल से बोर्ड को करीब 3.3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 31.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह राशि करीब 40 करोड़ बांग्लादेशी टका बैठती है।

**मनोरंजन | बॉलीवुड का कोना**

## विधात्री बंदी की 'कैरोल' तक पहुंचने की कहानी है बेहद खास

# जिस किरदार को दिल से मांगा, वही मिल गया!

अभिनेत्री विधात्री बंदी इन दिनों अपनी फीचर फिल्म 'मैक्स, मिन और मियोज्स्की' में निभाए गए कैरोल सेक्षेराका के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस भूमिका के लिए उन्होंने शुरुआत से ऑडिशन नहीं दिया था। वह फिल्म में 'मिन' का किरदार हासिल करने के इरादे से ऑडिशन देने पहुंची थीं, लेकिन कहानी का सार पढ़ते ही उनका ध्यान कैरोल की ओर चला गया। विधात्री ने बताया कि कैरोल का किरदार जिस तरह लिखा गया था, उससे वह तुरंत जुड़ गईं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर इस भूमिका के लिए मौका मिला तो वह जरूर कोशिश करेंगी। उन्होंने यह इच्छा किसी से साझा भी नहीं की।

अभिनेत्री के मुताबिक, ऑडिशन देने के महज दो दिन बाद कास्टिंग टीम का फोन आया। उन्हें बताया गया कि निर्देशक चाहते हैं कि वह कैरोल के किरदार के लिए ऑडिशन दें। विधात्री ने ऑडिशन दिया और उनका चयन तुरंत हो गया। इसके बाद निर्देशक पैडी ने उन्हें फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनते वक्त अभिनेत्री इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बताया कि अजनबियों के सामने इस तरह भावुक होना उनके लिए असामान्य अनुभव था। उसी पल उन्हें महसूस हुआ कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। विधात्री ने बताया कि कैरोल का लुक उनके अब तक निभाए गए किरदारों से काफी अलग है। फिल्म 'जलसा' में वह एक मलयाली पत्रकार के रूप में नजर आई थीं। उस किरदार के लिए उन्होंने बिना मेकअप, भारी लहजे और अलग हेयर लुक के साथ काम किया था। वहीं 'द डिप्लोमैट' में उन्होंने पंजाबी दूतावास अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसमें उनका पहनावा काफी औपचारिक था।

### धीमी रही रफ्तार, लेकिन हर कदम आगे बढ़ा

विधात्री ने अपने करियर को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका सफर तेज गति से नहीं बढ़ा, बल्कि हर प्रोजेक्ट के साथ धीरे-धीरे आगे आया। 'शिद्दत' में छोटे रोल से शुरुआत करने के बाद 'जलसा' में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसके बाद 'द डिप्लोमैट' में लीड भूमिका निभाई और अब 'मैक्स, मिन और मियोज्स्की' में वह प्रमुख किरदार में हैं। अभिनेत्री के लिए यह सफर भले धीमा रहा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि वह लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनका मानना है कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है हर कदम का सही होना।

## प्रीति जिंटा का नया 'वाइब' मचा रहा हलचल, एक्शन और दोस्ती के तूफानी सफर में दिखेगा अलग अंदाज

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री जल्द ही हाई-स्टेक्स एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' में दिखाई देंगी। फिल्म को लेकर शुक्रवार को प्रीति ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट साझा किया, जिसने उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी। तस्वीर में अभिनेत्री ब्लैक ओवरसाइज्ड टी-शर्ट और चंकी सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं।

प्रीति जिंटा ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए जिंदगी, ठहराव और नए अनुभवों को लेकर एक खास संदेश लिखा। उनके इस अंदाज को फिल्म 'वाइब' से जोड़कर देखा जा रहा है। पोस्ट सामने आने के बाद प्रशंसक फिल्म में उनके किरदार और कहानी को लेकर कयास लगाने लगे हैं। फिल्म की कहानी दो बेहद करीबी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की सामान्य जिंदगी अचानक एक ऐसे रोमांचक और अप्रत्याशित सफर में बदल जाती है, जहां हर मोड़ पर नई चुनौती उनका इंतजार करती है। इस दौरान दोस्ती, हिम्मत और जिंदगी को लेकर उनका नजरिया भी परीक्षा से गुजरता है।

'वाइब' को अभिनेता कुणाल खेमू ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण कुणाल खेमू और चिराग निहलानी की ड्रेंगो फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ खुद कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वंशिका धीर इस फिल्म के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं। फिल्म को 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की तैयारी है।

**मेट्रो बाजार**

# चीन के बाद भारत एपीएसी में सबसे बड़ा डेटा सेंटर मार्केट

**नई दिल्ली।** भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र (एपीएसी) में चीन के बाद सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बनकर उभरा है। पिछले छह वर्षों में देश की लाइव आईटी क्षमता चार गुना बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी डेटा में दी गई। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस (बीएनईएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन मौजूद है। देश में 1.3 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 3.2 गीगावाट की अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन, बिजली और निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल की जा चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ÷ऊर्जा की उपलब्धता और फाइबर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत स्थिति भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा स्थान बनाती है।÷ महाराष्ट्र भारत का सबसे प्रमुख डेटा सेंटर बाजार बना हुआ है। देश में लाइव आईटी क्षमता के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है और कुल क्षमता में इसकी हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल कर चुकी परियोजनाओं की सबसे बड़ी पाइपलाइन भी महाराष्ट्र में है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्षेत्र के अगले चरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कंपनियां इन राज्यों में बड़े निवेश और परियोजनाओं की घोषणा कर रही हैं। घरेलू कारोबारी समूहों ने भारत में डेटा सेंटर विकास के लिए 210 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जो कुल घोषित निवेश का 45 प्रतिशत है।

# रक्षाबंधन पर देश में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है व्यापार

**मुंबई।** रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते विश्वास और राष्ट्रभावना का भी उत्सव बन गया है। देशभर के बाजारों में स्वदेशी राखियों की अच्छी मांग देखी जा रही है और विभिन्न राज्यों में तैयार की गई विशिष्ट भारतीय राखियां उपभोक्ताओं का विशेष आकर्षण बनी हुई हैं।

कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत अधिक है जबकि उपहार, मिठाई, वस्त्र एवं अन्य त्योहारी उत्पादों को मिलाकर कुल व्यापार 30 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच सकता है।पिछले वर्ष राखी का व्यापार देश भर में लगभग 17 हज़ार रुपए का हुआ था वहीं वर्ष 2023 में यह व्यापार 12 हज़ार करोड़ रुपये का हुआ था। कैट के अनुसार देशभर के बाजारों में इस वर्ष भी चीनी राखियों की कोई मांग नहीं है। व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं ने पूरी तरह स्वदेशी राखियों को अपनाया है और बाजारों में केवल भारतीय निर्मित राखियां ही उपलब्ध हैं। कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। कैट का मानना है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते रुझान और वोकल फॉर लोकल÷ अभियान के कारण भारतीय कारीगरों, महिला उद्यमियों, लघु उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों को इस रक्षाबंधन पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

# यह है 12-बोर की पंप-एक्शन शॉटगन, जम्मू-कश्मीर में हुआ था व्यापक इस्तेमाल

दोपहर मेट्रो एक्सप्लेनर

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैलेट गन इन दिनों फिर चर्चा में है। आखिर यह हथियार है क्या और इसे लेकर इतना विवाद क्यों है?

भारत में पैलेट गन का सबसे चर्चित इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में 2010 के व्यापक प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुआ। इसे पारंपरिक जिंदा गोलियों के मुकाबले कम-घातक विकल्प माना गया, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और नागरिक मौतें कम हों। सरकारी रिकॉर्ड में भी यूपीए सरकार के दौरान जम्मू-कश्मीर को 2010-11 में एंटी-रायट गन और गैर-घातक हथियार उपलब्ध कराने का उल्लेख मिलता है।

**पैलेट गन मूलतः** 12-बोर पंप-एक्शन शॉटगन होती है। इसके कारतूस में एक गोली के बजाय बड़ी संख्या में छोटे धातु के छर्रे होते हैं।

## जंतर मंतर पर पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विवाद और सुर्खियां

फायर होने पर ये छर्रे फैलते हुए लक्ष्य की ओर जाते हैं। यही इसकी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। इसे 'कम-घातक' कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ कतई यह नहीं कि यह घातक नहीं है। दुनिया में भीड़ नियंत्रण के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नया नहीं है। उत्तरी आयरलैंड की दिक्कतों के दौरान 1970 के दशक में ब्रिटिश सुरक्षा बलों ने रबर और बाद में प्लास्टिक बुलेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों को भी पारंपरिक गोलियों का कम-घातक विकल्प बताया गया था, लेकिन उनसे गंभीर चोटें आईं और मौतें भी हुईं।

भारत में पैलेट गन का सबसे बड़ा विवाद 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा के दौरान हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की आंखों और शरीर के दूसरे हिस्सों में छर्रे लगे। इसके बाद पैलेट गन को लेकर मानवाधिकार और सुरक्षा—दोनों दृष्टिकोणों से तीखी बहस शुरू हुई। सरकार ने जुलाई 2016 में इसके विकल्प तलाशने के लिए विशेषज्ञ समिति भी बनाई। 2018 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि पैलेट-फायरिंग शॉटगन का इस्तेमाल जारी था और इसके इस्तेमाल के लिए सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था।

असल सवाल यही है कि क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसा हथियार उचित है? पैलेट गन गोली नहीं चलाती, लेकिन उसके सैकड़ों छर्रे मिलकर किसी व्यक्ति की जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। इसलिए सवाल केवल यह नहीं कि पैलेट गन कितनी कम घातक है; सवाल यह भी है कि लोकतंत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए इससे बेहतर, अधिक सटीक और कम नुकसानदेह विकल्प हमारे पास क्यों नहीं हैं।

### पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एडवाइजरी के तहत असाधारण परिस्थितियों में भीड़ नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स के हिस्से के रूप में इसका सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से पैलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर और मानक संचालन प्रक्रिया पेश करने को कहा है। जंतर मंतर पर पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति पैलेट गन के साथ इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित अत्यधिक इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा घायलों को चिकित्सा सहायता और मुआवजे जैसे पहलुओं की भी जांच करेगी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत अब केवल पैलेट गन के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि कब, कितना और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल उचित माना जाए, इस मूल प्रश्न की भी समीक्षा कर रही है।

## झांगजियाजी की हाई-एल्टीट्यूड जिपलाइन

**चीन के झांगजियाजी** में रोमांच पसंद करने वालों के लिए हाई-एल्टीट्यूड जिपलाइन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच हवा में झूलती यह जिपलाइन पर्यटकों को अनोखा अनुभव देती है। यहां सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पहाड़ी इलाके का नजारा देखते हुए सफर किया जा सकता है। नीचे फैली हरियाली, ऊंची चट्टानें और संकरी घाटियां इस रोमांच को और खास बना देती हैं। जिपलाइन से गुजरते समय पर्यटकों को ऐसा महसूस होता है, जैसे वे पहाड़ों के बीच आसमान में उड़ रहे हों। झांगजियाजी में यह एडवेंचर एक्टिविटी पर्यटकों के लिए रोमांच और प्रकृति का शानदार संगम बन गई है।

### 6 माह से जारी जंग के बीच तेहरान का बदला रुख, बीजिंग ने अमेरिकी दबाव ठुकराकर बातचीत की पैरवी की

# ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का ऐलान, आ गया जंग खत्म करने का समय

**तेहरान, एजेंसी**

ईरान-अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पहली बार युद्ध खत्म करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ईरान मजबूत और सम्मानजनक स्थिति में है, इसलिए अब जंग रोकना बेहतर होगा। उनका यह बयान चीन के सक्रिय होने के बाद आया है। बीजिंग ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।

पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल पर ईरान के स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जून में अमेरिका के साथ हुए समझौते का बचाव करते हुए कहा कि इसमें ईरान के आत्मसमर्पण जैसी कोई शर्त नहीं है। उधर, अमेरिका ने सैन्य दबाव के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान पर शिकंजा कसना शुरू किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे 'आर्थिक आतंकवाद' बताया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी 'इकोनॉमिक डी-डे' योजना को घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। सबसे बड़ा बदलाव चीन के रुख से आया है। बीजिंग ने अमेरिकी एकतरफा प्रतिबंधों की नीति का विरोध करते हुए बातचीत को समाधान का रास्ता बताया है। आगामी शी जिनपिंग-डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में ईरान का मुद्दा अहम रहने की संभावना है। इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हल की उम्मीद जरूर बढ़ी है।

### हम मजबूत स्थिति में हैं- ईरान

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरान मजबूत और सम्मानजनक स्थिति में है, इसलिए अब युद्ध को रोकना बेहतर होगा। उनके मुताबिक, संघर्ष को आगे बढ़ाने से तबाही बढ़ने का खतरा है। पेजेशकियान ने अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने और ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। हालांकि, उन्होंने अपने देश को युद्ध में कमजोर मानने से साफ इनकार किया। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव के साथ कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। राष्ट्रपति के इस रुख को ईरान की ओर से युद्धविराम की दिशा में पहला महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

### चीन ने बदला ईरान-अमेरिका संघर्ष का समीकरण

ईरान-अमेरिका संघर्ष में चीन की सक्रियता ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दिया है। बीजिंग ने अमेरिका की उस नीति का समर्थन करने से इनकार किया है, जिसमें ईरान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि एकतरफा प्रतिबंधों और दबाव से पश्चिम एशिया की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। चीन के इस रुख से अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। साथ ही, ईरान को भी बातचीत की मेज पर आने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में बीजिंग की भूमिका आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

### अमेरिका-चीन वार्ता में ईरान अहम मुद्दा

**ईरान संकट** अब अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच भी बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन ने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव की नीति का समर्थन करने के बजाय बातचीत और संयम पर जोर दिया है। इससे वाशिंगटन और बीजिंग के बीच मतभेद और स्पष्ट हो सकते हैं। वहीं, आगामी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में ईरान का मुद्दा महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। चीन का ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध है, जबकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में दोनों महाशक्तियों की बातचीत का असर युद्ध की दिशा पर पड़ सकता है। यदि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं, तो लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को रोकने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

# हाइवे किनारे ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को बस ने रौंदा, 5 की मौत, 5 गंभीर घायल

**पटना, एजेंसी**

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया-लौरिया मुख्य मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से बेतिया की ओर जा रही तेज रफ्तार शाही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे छठिहार समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देख रहे लोगों की भीड़ में जा घुसी। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र दुबे के घर पर शुक्रवार को छठिहार समारोह का आयोजन किया गया था। उनका घर एनएच-727 के किनारे स्थित है। समारोह के दौरान घर के बाहर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के कई लोग सड़क किनारे जुटे हुए थे। इसी दौरान लौरिया की ओर से बेतिया जा रही शाही बस तेज रफ्तार में वहां पहुंची और अचानक

अनियंत्रित होकर लोगों की भीड़ में जा घुसी। बस की चपेट में आने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के वक्त बेतिया की ओर से गैस सिलेंडर लदा एक ट्रक भी आ रहा था, जबकि दूसरी ओर से शाही बस बेतिया की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई।

## नितिन नवीन की नई भाजपा टीम के साथ पहली बैठक

**नई दिल्ली, एजेंसी**

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी की 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ और जमीनी स्तर पर

संगठन मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

यह बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए गए। नितिन नवीन आज क्ष्छ्क्शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। नितिन नवीन ने 17 अगस्त को 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान किया था। इनमें 51 नए चेहरे शामिल हैं। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं। नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला बड़ा संगठनात्मक फेरबदल है।

### सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

# तीन नहीं, अब एक साल की वकालत कर बन सकेंगे जज

**नई दिल्ली, एजेंसी**

न्यायिक सेवा में प्रवेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त बनाए रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने बार में जरूरी प्रैक्टिस की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक और शर्त लगाई है। इसके तहत न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को एक साल का गहन प्रशिक्षण राज्य न्यायिक अकादमी में लेना होगा। इसके बाद छह महीने जिला न्यायाधीश/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ क्लर्कशिप और छह महीने किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण अवधि के संबंध में भी महत्वपूर्ण छूट दी है, जो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। अदालत ने कहा, निर्देश यह है कि तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता के बावजूद सभी कानून स्नातक आवेदन करने के पात्र होंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि समीक्षा के तहत फैसले को सुनाए जाने के बाद एक साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक साल की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी कर लेने वाला माना जाएगा और उन्हें इस अवधि के लिए प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खुली अदालत में उन समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिनमें न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य करने वाले उसके फैसले को चुनौती दी गई थी।

### सीजेआई सूर्यकांत ने की थी क्या टिप्पणी?

अदालत ने कहा था कि तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए एक खाली अवधि पैदा करती है। इससे प्रतिभाशाली उम्मीदवार कानून की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा को करियर के विकल्प के रूप में चुनने से हतोत्साहित हो सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें युवा प्रतिभाओं पर इसके प्रभाव को भी देखना होगा। हम इसे इस तरह कैसे लागू करें कि इससे प्रतिभाशाली उम्मीदवार वंचित न हों? आज कानून की पढ़ाई पूरी करने वाला नया स्नातक पात्र नहीं है।'' महिला उम्मीदवारों के सामने आने वाली सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी सीजेआई ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस शर्त का असर महिला न्यायिक अधिकारियों की तैयारी कर रही उम्मीदवारों पर ज्यादा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ''लड़कियां वास्तव में परेशान हैं। लड़कियां हमारी प्रतिभा की क्षमता हैं।'' उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के दबाव, शादी और स्थान बदलने जैसी परिस्थितियों के कारण कई महिलाएं जरूरी वर्षों की प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाएं, ऐसी आशंका है।

**मेट्रो एंकर**

### नासा की रिपोर्ट में सामने आया 'वार्मिंग होल'

# भारत में ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार दुनिया से धीमी

**वॉशिंगटन, एजेंसी**

दुनिया में बढ़ते तापमान और लगातार टूटते गर्मी के रिकॉर्ड के बीच नासा के आंकड़ों से भारत को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक तापमान बढ़ने की तुलना में भारत में गर्मी बढ़ने की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है। वैज्ञानिक इस प्राकृतिक स्थिति को 'वार्मिंग होल' के नाम से संदर्भित करते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 1980 के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वहीं, भारत में 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक तापमान वृद्धि 0.9 डिग्री सेल्सियस से कम बताई गई है। नासा के तापमान

मानचित्र में भी भारत का बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों की तुलना में हल्के रंगों में दिखाई देता है, जहां गर्मी में अधिक वृद्धि हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सिंचाई इस अंतर की एक वजह हो सकती है। सिंचाई से वातावरण में नमी बढ़ती है, जिससे स्थानीय तापमान पर असर पड़ता है। इसके अलावा, वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कण सूर्य की कुछ ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर सकते हैं। हालांकि, तापमान वृद्धि की धीमी रफ्तार के बावजूद भारत में मौसम संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। देश के करीब 18 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में तेज हवाओं, बिजली और अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया है।

**सिंचाई और प्रदूषण का तापमान पर असर :** वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में तापमान बढ़ने की अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार के पीछे कई स्थानीय और क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर होने वाली सिंचाई उनमें प्रमुख मानी जाती है। खेतों में पानी पहुंचने से वातावरण में नमी बढ़ती है, जिससे वाष्पीकरण के जरिए सतह के तापमान पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, वातावरण में मौजूद एरोसोल यानी बेहद छोटे कण सूर्य की कुछ किरणों को परावर्तित कर अंतरिक्ष की ओर भेज सकते हैं। इससे धरातल तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा घट सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इन कारकों के प्रभाव को व्यापक जलवायु बदलाव के संदर्भ में समझना जरूरी है। कम वार्मिंग का मतलब यह नहीं कि भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया**
**स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 ( *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564, 4917524